संस्थापक :स्व.श्री वीर विक्रम आदित्य

स्थापना वर्ष : 2002

हिन्द जनपथ

पंचकूला
रविवार
14 दिसम्बर 2025
वर्ष : 24 अंक : 171
कुल पृष्ठ : 08
मूल्य : एक रुपया

खबरें छापते हैं छुपाते नहीं

दैनिक प्रभात संस्करण हरियाणा,पंजाब,हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रकाशित।

www.hindjanpath.com

● फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद बड़ा ऐक्शन

आयोजक अरेस्ट, दर्शकों के पैसे लौटाए जाएंगे

कोलकाता (एजेंसी)। साल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को आयोजित लियोनेल मेस्सी के फुटबॉल कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आयोजन स्थल पर मची व्यापक अफरा-तफरी के बाद यह कदम उठाया गया। इसके चलते अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेस्सी को मैदान छोड़कर समय से पहले ही लौटना पड़ा। दत्ता को आयोजन के कथित तौर पर कुप्रबंधन के आरोप में कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वह मेस्सी और उनके साथ शामिल अन्य को हैदराबाद जाते समय विदा करने गए थे। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

दिया है और कहा है कि मामले की पूरी जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शकों को टिकट के पैसे वापस मिलने चाहिए। दरअसल शनिवार को पूरा कोलकाता मेसी के स्वागत में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, तस्वीर बदल गई। साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को लेकर भारी अव्यवस्था थी। हजारों रुपये खर्च करके टिकट खरीदने के बावजूद कई प्रशंसक अपने चहेते खिलाड़ी को देख भी नहीं पाए। मेसी भी तय समय से पहले ही मैदान छोड़कर चले गए। इससे मेसी के प्रशंसकों का गुस्सा फूट पड़ा और स्टेडियम रणक्षेत्र बन गया। स्टेडियम में बोतलें फेंकी गईं, कुर्सियां उड़ीं, और फेंसिंग के गेट तोड़कर सैकड़ों लोग मैदान में घुस गए। स्टेडियम में आग भी लग गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। सुरक्षाकर्मी भी बेबस नजर आए।

पुलिस कार्रवाई जारी, ममता ने मेस्सी से माफी मांगी

जावेद शमीम ने बताया कि एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आयोजक को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कौन दोषी है। यह जांच के बाद ही पता चलेगा। इसमें कुछ समय लगेगा। जिन मेसी प्रशंसकों के साथ धोखा हुआ है और जो गुस्से में हैं, उनकी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम में हुए कुप्रबंधन पर हैरानी जताते हुए इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। ममता ने कहा कि वह मेस्सी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सॉल्टलेक स्टेडियम जा रही थीं, जहां हजारों प्रशंसक खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे।

अल-फलाह स्टूडेंट्स-स्टाफ को घरों से निकाल रहे मालिक

दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर आने का डर

फरीदाबाद (एजेंसी)। दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़ने के बाद से जांच के दायरे में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स व स्टाफ के लिए नई दिक्कत पैदा हो गई है। जो स्टूडेंट्स या स्टाफ आस-पास के इलाकों में किराये पर रह रहे हैं, उन्हें मकान खाली करने को कहा जा रहा है। मकान मालिकों को जांच एजेंसियों के रडार पर आने का डर है। दरअसल, कैंपस के बाहर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स पीजी या किराये पर कमरे लेकर रह रहे हैं। अब मकान मालिक इन्हें कमरे खाली करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इसकी बड़ी

वजह यही है कि जांच एजेंसियों की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई के चलते कोई भी मकान मालिक परेशानी में फंसना नहीं चाहता। क्योंकि, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ कर रही है। आतंकी नेटवर्क में शामिल डॉ शाहीन सईद, डॉ. मुजम्मिल शकील और सुसाइड बाम्बर बने डॉ उमर नबी के संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ अभी तक जारी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दो हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी से हैं।

यूपी बीजेपी के नए 'चौधरी' होंगे पंकज

योगी प्रस्तावक रहे, निर्विरोध चुना जाना तय

7 बार से महाराजगंज से सांसद, केंद्र में मंत्री

कोलकाता (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने राजधानी लखनऊ

स्थित भाजपा कार्यालय में आज अपना नामांकन दाखिल किया। चूंकि, नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा दोपहर 3 बजे तक थी और इस दौरान किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसलिए अब मोदी-शाह के करीबी चौधरी का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। अब रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। गोयल के अलावा विनोद तावड़े भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए शनिवार को ही दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। इससे पहले यूपी भाजपा के नए बॉस पर सस्पेंस के बीच मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिना नाम लिए बड़ा खुलासा कर दिया था।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को पाकिस्तान से खतरा

● गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई, भोपाल-दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग

भोपाल (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली- दोनों जगह उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया। भोपाल में 74 बंगला स्थित बी-8 आवास के चारों

तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग की। वहीं दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिवराज पर पाकिस्तान के की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से दिलचस्पी दिखाने की जानकारी मिली है। सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जारी गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है।

इंडिगो की मोनोपॉली कैसे बनी, इसकी जांच होगी

● ताकत के गलत इस्तेमाल का लगा आरोप, सरकार हो गई ऐक्टिव ● एविएशन सेक्टर में 65फीसदी हिस्सेदारी, रोजाना 2,200 उड़ानें

नई दिल्ली (एजेंसी)। एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइन की मोनोपॉली (एकतरफा दबदबा) अब जांच के दायरे में आ गई है। देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने मोनोपॉली बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इंडिगो संकट कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कॉम्पिटिशन कमीशन अंदरूनी तौर पर इंडिगो की मोनोपॉली वाली स्थिति, खास रूट्स पर दबदबे और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन कर रहा है। किराया

बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। डीजीसीए की ओर से एविएशन नियमों में बदलाव चलते भारी दिक्कत हो गई।

पश्चिम एशिया में शांति और पहलगाम पर जॉर्डन का विरोध

किंग अब्दुल्ला-मोदी की मीटिंग पर दुनिया के कई देशों की नजरें

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 15 से 18 दिसंबर तक तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना, आपसी सहयोग के नए रास्ते तलाशना और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी

जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात कर भारत-जॉर्डन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, यह यात्रा भारत की विदेश नीति के लिए एक अहम कदम है, जिससे कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बता दें कि जॉर्डन के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में जॉर्डन का मुखर समर्थन इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है। **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भूमिका-** प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र अशांति से गुजर रहा है।

'जंग' भाषणों से नहीं ऐक्शन से जीती जाती है

● सीडीएस बोले-पाकिस्तान हमेशा जीत के झूठे दावे करता रहा है, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा

हैदराबाद (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि युद्ध केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई से जीते जाते हैं। सीडीएस तेलंगाना के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स अकादमी में ऑटम टर्म दिसंबर 2025 की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा-खाली शब्दों और प्रतीकात्मक दावों से ताकत साबित नहीं होती। अनुशासन, ठोस योजना और निर्णायक अमल ही किसी देश की असली सैन्य क्षमता दिखाते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर तंज

कसते हुए कहा कि हाल के समय में वहां झूठे जीत के दावे और सोशल मीडिया प्रचार देखने को मिले, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और रही है। नए अधिकारी ऐसे समय सेवा में आ रहे हैं, जब ऑपरेशन 'सिंदूर' जारी है। मौजूदा सुरक्षा माहौल में हर समय सतर्कता, फुर्ती और तैयार रहना जरूरी है।

'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' में अब 125 दिनों काम

● पहले यह योजना मनरेगा या नरेगा के नाम जानी जाती थी ● का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की रोजी-रोजी की सुरक्षा बढ़ाना है

नई दिल्ली (एजेंसी)। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक्ट का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मनरेगा या नरेगा के नाम से जाना जाता है। यह सरकार की एक खास स्कीम है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की रोजी-रोटी की सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत हर उस परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों की गारंटी वाली मजदूरी वाला काम दिया जाता है, जिसके बड़े सदस्य बिना हुनर का काम

करने के लिए अपनी मर्जी से तैयार होते हैं। इसे 2005 में लागू किया गया था।

वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे का तर्क समझ नहीं आता। जिससे फिजूल खर्च होता है। उन्होंने कहा- मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। सबसे पहले, यह महात्मा गांधी का नाम है, और जब इसे बदला जाता है, तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। ऑफिस से लेकर स्टेशनरी तक, सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, इसलिए यह एक बड़ी, महंगी प्रक्रिया है। तो ऐसा करने का क्या फायदा है।

कांग्रेस बोली- मोदी सरकार ने हमारी 32 योजनाओं के नाम बदले

कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का नाम बदल कर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रखा है। इसी मनरेगा को मोदी कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा बताते थे लेकिन असलियत यह है कि यही मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ। कांग्रेस की स्कीमों का नाम बदल कर उनको अपना बना लेने की मोदी जी की यह लत बड़ी पुरानी है यही तो किया है उन्होंने 11 साल, यूपीए की स्कीमों का नाम बदल अपना ठप्पा लगा कर पब्लिसिटी करना। सुप्रिया ने एक्स पर उन योजनाओं के नाम शेयर किए हैं, जिन्हें कांग्रेस ने शुरू किया था। साथ ही दावा किया है कि इनके नाम बदले गए हैं। केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना करने की खबरों पर शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा-फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। यह ध्यान भटकाने का एक और तरीका है। वंदे मातरम पर चर्चा से जनता को समझ आ गया है कि इतिहास का वॉट्सएप वर्जन कौन सा है और असली वर्जन कौन सा है।

बंगाल में लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे

● ममता की भवानीपुर सीट में 44 हजार नाम डिलीट ● साउथ 24 परगना जिले से टोटल 8 लाख नाम कटे

कोलकाता (एजेंसी)। चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के पहले फेज के बाद निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक, राज्य में 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। सीएम ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से 44,787 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यहां जनवरी 2025 की लिस्ट में 1,61,509 वोटर्स थे। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम

सीट से 10,599 नाम हटाए गए। यहां एसआईआर से पहले 2,78,212 वोटर थे। जिलावार आंकड़ों में साउथ 24 परगना सबसे ऊपर रहा, जहां 8 लाख 16 हजार से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए है। यह इलाका टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। उन्होंने डायमंड हार्बर सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में सात लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ, बंगाल भाजपा के को-इंचार्ज अमित मालवीय ने दावा किया है कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले फेज के आखिरी दिन अपना फॉर्म भर दिया है।

अब यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को मिलाकर होगा एक बोर्ड

● केंद्रीय कैबिनेट ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल' को मंजूरी दी, मेडिकल-लॉ स्टडीज पर लागू नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हायर एजुकेशन के लिए देश में एक बोर्ड होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे पुराने नियामकों को एक कर

दिया जाएगा। हालांकि, मेडिकल और लॉ स्टडीज इसके दायरे से बाहर रहेंगी। ये विधेयक मौजूदा संसद सत्र में ही बहस के लिए पेश किया जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक कॉमन कमीशन बनाने की बात कही गई थी जो देश में अलग-अलग हायर एजुकेशन संस्थाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाए।

● **संस्थानों की फंडिंग नए बोर्ड के तहत नहीं आएगी-** नए कानून के तहत हायर एजुकेशन को स्पष्ट कार्य-विभाजन के साथ रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। संस्थानों का रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और शैक्षणिक मानक निर्धारण का काम एक बोर्ड के पास होगा। वहीं फंडिंग को इस रेगुलेटर से अलग रखा गया है। फंडिंग अभी भी संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के तहत रेगुलेट होगी। भारत सरकार 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी। सरकार का दावा था कि इसमें क्लास 6 से ही वोकेशनल स्टडीज मिलने से सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के अवसर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेंगे।

शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन की नई इबारत, मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा निदेशालय में अत्याधुनिक शैक्षणिक अवसंरचना का लोकार्पण किया

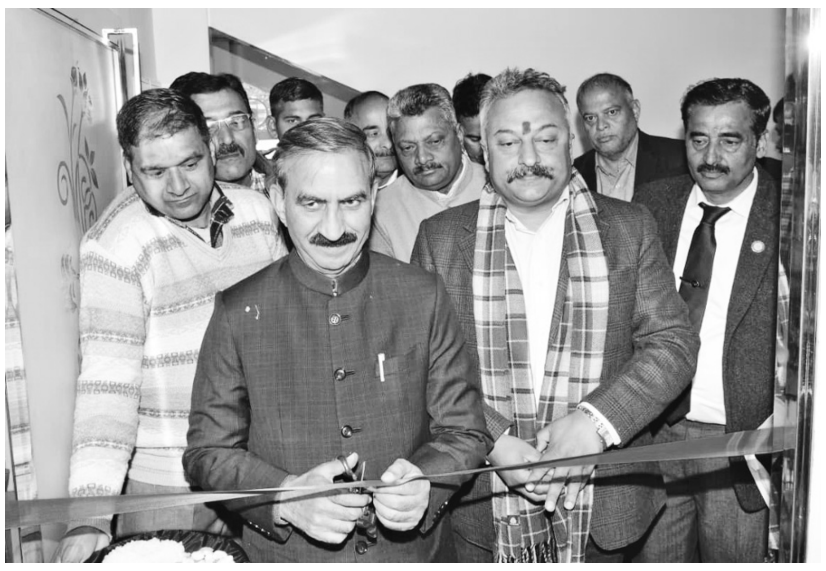

प्रदेश सरकार विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रयासरतः ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज समग्र शिक्षा निदेशालय में नव-निर्मित विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियोदूसम्मेलन क्षेत्र, नए सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधाएं न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करेंगी। यह पहल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है, जिसमें शिक्षा को विकास की रीढ़ माना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक निर्णायक सुधार लागू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन में हिमाचल प्रदेश ने 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार करते हुए पांचवां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सामूहिक मेहनत के साथ-साथ प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र इस परिवर्तनकारी यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। हिमाचल प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहां एकीकृत डिजिटल मंच के माध्यम से शिक्षण, मूल्यांकन, उपस्थिति, संसाधन प्रबंधन और विद्यालय संचालन से संबंधित वास्तविक समय का आंकड़ा उपलब्ध करवाया जा रहा है। 'अभ्यास हिमाचल', भू-स्थानिक तकनीक आधारित स्मार्ट उपस्थिति प्रणाली तथा 'निपुण प्रगति' जैसे नवाचार विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का वैज्ञानिक विश्लेषण सुनिश्चित कर रहे हैं। अब सीखने की कमियों की पहचान अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों के माध्यम से की जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणाम-केंद्रित बन रही है।

उन्होंने कहा कि 'शिक्षक सहायक' डिजिटल उपकरण शिक्षकों के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण सामग्री, दिशा-निर्देश और शैक्षणिक संसाधन त्वरित रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ प्रशासनिक बोझ में भी कमी आई है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल नए संस्थान स्थापित करना नहीं है, बल्कि मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त, सक्षम और आधुनिक बनाना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी समान रूप से पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा। अध्यापक अपने मोबाइल फोन स्टाफ रूम या बैग में रख सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में दृढ़ता से कार्य किया जा रहा है। स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत, संस्कृति और भविष्य के विषयों का समावेश भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर भर्तियां करने जा रही है, जिसमें अस्थाई व स्थाई दोनों तरह की भर्तियां की जाएंगी। अस्थाई भर्तियां पांच वर्ष के लिए व स्थाई भर्तियां बैच वाइज व प्रतिस्पर्धा के आधार पर की जाएंगी। मल्टी यूटिलिटी वर्कर्ज की भर्ती भी की जाएगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्राथमिक विद्यालयों की खेल प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2032 तक प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में देश के सबसे बेहतरीन स्कूल होंगे। हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में नंबर एक स्थान पर होगा। प्रदेश सरकार द्वारा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना बहुआयामी दृष्टिकोण से की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में बेहतर तबादला नीति लाने पर विचार किया जा रहा है। राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूलों के लिए विशेष कैडर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को शिक्षा विभाग से सबसे अधिक सहयोग प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संकल्प वर्कबुक का विमोचन भी किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। प्रदेश सरकार ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किए हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए क्लस्टर स्कूल प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत 300 से 500 मीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों को एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है। इस मॉडल ने पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल सामग्री और शिक्षकों की विशेषज्ञता का साझा उपयोग संभव बनाया है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और सीखने के अनुभव दोनों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में भी हिमाचल का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से उभरा है। मेधावी छात्रों के लिए जेईई और एनईईटी कोचिंग की मुफ्त सुविधा प्रदेश सरकार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम है। यह पहल सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक स्थिति किसी भी बच्चों के भविष्य के रास्ते में बाधा ना बने। उन्होंने शिक्षा विभाग की विभिन्न पहलों का विस्तार से वर्णन किया।

परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा ने समग्र शिक्षा की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश ने विभिन्न सर्वेक्षणों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिक्षकों को आईआईटी और आईआईएम में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शिक्षण कौशल को और निखारने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

भविष्य उन्मुख शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए यूनेस्को के साथ हिमाचल प्रदेश फ्यूचर्स प्रोग्राम के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा तंत्र में नवाचार, सतत विकास लक्ष्य और वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

सोलन ज़िला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए 6597 मामले

सोलन। प्रदेश के साथ-साथ आज सोलन ज़िला के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सोलन ज़िला के सभी न्यायालयों में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 6597 मामलों का निपटारा विभिन्न पक्षों की आपसी सहमती से किया गया। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के अन्तर्गत उपमण्डल नालागढ़, कसौली, अर्की तथा सोलन मुख्यालय में 13 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि इस दिसम्बर माह मे प्री लोक अदालत सीटिंगस भी करवाई गई। इन लोक अदालतों का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन शरद कुमार लगवाल की अध्यक्षता में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि इस अवसर पर कुल 8620 मामलों को सुनवाई के लिए प्री लोक अदालत सीटिंगस एवं लोक अदालत की विभिन्न बैंचों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इनमें से 6597 मामलों का निपटारा विभिन्न पक्षों की आपसी सहमति से किया गया। इन मामलों में कुल 9,86,92,129 रुपये समझौता राशि रही।

उन्होंने कहा कि इन मामलों में 7533 मोटर वाहन चालानों भी विभिन्न बैंचों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुल 5873 मामलों का निपटारा सुनिश्चित बनाया गया।

प्रदेश सरकार के चिट्टा मुक्त अभियान को मिली गति

राज्यभर में विशेष अभियान के अंतर्गत 254 एकांत स्थलों का निरीक्षण एवं 596 वाहनों की ली तलाशी

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा शुक्रवार को राज्य-स्तर पर एक विशेष, सुनियोजित एवं सघन अभियान संचालित किया गया। यह अभियान प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवंबर से शुरू किए गए राज्यव्यापी एंटी-चिट्टा जन-आंदोलन के अंतर्गत 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिगत चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में चिन्हित एकांत एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थलों जैसे सुनसान पहाड़ी ढलानें, जंगलों के हिस्से, खाली भवन, कमरे, पार्किंग स्थल, नदी-नाले के किनारे, पुराने बस-स्टैंड, गैराज शेड आदि का व्यापक निरीक्षण एवं गहन तलाशी की गई।

इस राज्य-स्तरीय अभियान के दौरान प्रदेश भर में कुल 254 निर्जन एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थलों का पुलिस द्वारा आकस्मिक एवं सघन निरीक्षण किया गया तथा 596 वाहनों की तलाशी ली गई। यह अभियान सभी पुलिस रेंजों में समान रूप से प्रभावी ढंग से संचालित किया गया, जिससे इस अभियान का महत्त्व स्पष्ट होता है। इसके तहत दक्षिणी रेंज में सोलन, किन्नौर, सिरमौर एवं बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में व्यापक तलाशी ली गई। केंद्रीय रेंज में मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, हमीरपुर एवं बिलासपुर जिलों में सघन निरीक्षण किया गया, जबकि उत्तरी रेंज में कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, चंबा एवं ऊना जिलों में चिन्हित स्थलों पर विशेष कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान 301 व्यक्तियों की जांच/काउंसलिंग की गई, जिनमें से नौ व्यक्तियों के रक्त/मूत्र के नमूने सुरक्षित किए गए। एनडीपीएस अधिनियम एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नौ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। साथ ही अभियान के दौरान एकांत अथवा सुनसान स्थलों पर पाए गए अन्य व्यक्तियों को समुचित परामर्श, आवश्यक दस्तावेजीकरण एवं काउंसलिंग के उपरांत उनके परिजनों को सौंपा गया।

यह राज्य-स्तरीय एंटी-चिट्टा अभियान पूर्णत व्यवस्थित, खुफिया-आधारित एवं अंतर-जिला समन्वय के साथ संचालित किया गया, ताकि विधि-सम्मत, सुरक्षित एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को चिट्टे तथा किसी भी प्रकार के नशे की लत की ओर बढ़ने से रोकना और ऐसे एकांत स्थलों पर विकसित हो रही समूह-आधारित नशा प्रवृत्तियों को समाप्त करना है, जो नए युवाओं को चिट्टे एवं नशे की ओर आकर्षित करती हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से चिट्टा एवं नशे से संबंधित सूचना को टॉल फ्री नंबर 112 या नजदीकी पुलिस थाना में देने का आग्रह किया। सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने एपीएआर सॉफ्टवेयर विकास की प्रगति की समीक्षा की

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) सॉफ्टवेयर के विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। यह सॉफ्टवेयर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी, प्रभावी एवं पूर्णतः डिजिटल प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि एपीएआर पोर्टल के माध्यम से एपीएआर तथा वार्षिक कार्य योजनाओं की एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग एक सुव्यवस्थित डिजिटल वर्कफ्लो के तहत की जा सकेगी। यह प्रणाली प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता, जवाबदेही तथा निगरानी में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि एपीएआर की शुरुआत संबंधित रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना एवं स्पष्ट रूप से निर्धारित गुणात्मक एवं मात्रात्मक लक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। सॉफ्टवेयर में यह प्रावधान भी होगा कि प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत अधिकारियों अथवा संपूर्ण कैडर के लक्ष्यों में वार्षिक संशोधन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान एवं मानकीकृत एपीएआर प्रारूप लागू किया जाएगा, जिससे प्रदर्शन मूल्यांकन में एकरूपता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। पोर्टल के माध्यम से एपीएआर की शुरुआत के समय रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एवं

एक्सेप्टिंग अधिकारियों की ऑनलाइन पहचान एवं अनुमोदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि यह प्रणाली एक ही वित्तीय वर्ष में एक से अधिक एपीएआर शुरू करने की सुविधा प्रदान करेगी, बशर्ते प्रत्येक एपीएआर की न्यूनतम अवधि तीन माह हो। इससे स्थानांतरण अथवा दायित्वों में परिवर्तन की स्थिति में अधिक सटीक मूल्यांकन संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रगति की समीक्षा करते हुए सॉफ्टवेयर को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा इसे उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एपीएआर पोर्टल प्रदर्शन-आधारित शासन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा सरकारी तंत्र में जवाबदेही की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन की नई इबारत

मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा निदेशालय में अत्याधुनिक शैक्षणिक अवसंरचना का लोकार्पण किया

प्रदेश सरकार विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रयासरतः ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज समग्र शिक्षा निदेशालय में नव-निर्मित विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियोदूसम्मेलन क्षेत्र, नए सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधाएं न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करेंगी। यह पहल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है, जिसमें शिक्षा को विकास की रीढ़ माना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक निर्णायक सुधार लागू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन में हिमाचल प्रदेश ने 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार करते हुए पांचवां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सामूहिक मेहनत के साथ-साथ प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र इस परिवर्तनकारी यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। हिमाचल प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहां एकीकृत डिजिटल मंच के माध्यम से शिक्षण, मूल्यांकन, उपस्थिति, संसाधन प्रबंधन और विद्यालय संचालन से संबंधित वास्तविक समय का आंकड़ा उपलब्ध करवाया जा रहा है। 'अभ्यास हिमाचल', भू-स्थानिक तकनीक आधारित स्मार्ट उपस्थिति प्रणाली तथा 'निपुण प्रगति' जैसे नवाचार विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का वैज्ञानिक विश्लेषण सुनिश्चित कर रहे हैं।

हर हाल में होगा गठबंधन, ऊपर से निर्देशः रविंद्र चव्हाण

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के पहले गठबंधन साथियों के बीच मची खींचतान ने महायुति पर दबाव को बढ़ा दिया है। अब इस दबाव को कम करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से निर्देश दिया गया है कि बड़े नगर निगम चुनावों के पहले हर हाल में गठबंधन कर लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मुंबई महानगरपालिका समेत 29 नगर निगमों के चुनाव जनवरी में होने की संभावना है, जबकि जिला परिषद के चुनाव मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से देर से हो सकते हैं। बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात करके वापस लौटे चव्हाण ने चुनाव के पहले गठबंधन को लेकर अपनी सहमति जताई।

आवश्यक सूचना

पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किये गये दावे उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

RNI NO: HARHIN/2002/08034, Postal Regd No. HR/AB/54/23-25 , स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक एकान्ति राय गर्ग द्वारा जनपथ पब्लिशर्स, बूथ नं.: 437-पी (बी.पी.पेट्रोल पंप के पीछे) सेक्टर-8, पंचकूला से प्रकाशित। **सम्पादकः- एकान्ति रॉय गर्ग,** मुख्य कार्यालयः बूथ नं: 437-पी (बी.पी.पेट्रोल पंप के पीछे) सेक्टर-8 पंचकूला-134109(हरियाणा)। मो.: 9915606900, email : hindjanpath@gmail.com, argarg1610@gmail.com ।

हिन्द जनपथ
पंचकूला
रविवार 14 दिसम्बर 2025

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं रोजगार देने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है : पंडित मोहन लाल बड़ौली

हमारे खिलाड़ी भारत का परचम विश्व में लहरा रहे हैं : बड़ौली

चंडीगढ़, । आदर्श युवा खेल एंड विकास समिति, नाहरी द्वारा शनिवार को छठे वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में खेल अधोसंरचना के विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सर्वश्रेष्ठ खेल नीति के कारण हमारे खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री बड़ौली ने कहा कि भाजपा सरकार ने मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, राज्य में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतकर देश व प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार खेलकूद को बढ़ावा दे रही है जिसकी बदौलत हमारे खिलाड़ी भारत का परचम विश्व में लहरा रहे हैं।

मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि युवा शक्ति सकारात्मक व रचनात्मक विचारों के साथ खेल, शिक्षा, कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए समाज व देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। श्री बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार युवाओं को हर तरह से प्रोत्साहित कर रही है। भाजपा सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए खेल व्यायशालाएं खोल रही हैं ताकि हमारे युवा खेल के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकें।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि नायब सैनी सरकार में विकास को निरंतर रफ्तार मिल रही है। बिना भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। नायब सैनी सरकार में युवाओं को मैरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और सभी वर्गों के लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम के विकास एवं बाढ़ से संबंधित कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक

चंडीगढ़, । हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम खंड के विकास एवं बाढ़ से संबंधित कार्यों को लेकर आज सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में तोशाम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण, बाढ़ के पानी की कोई प्राकृतिक निकासी नहीं है, और जल निकासी विशेष रूप से भिवानी-धम्गर ड्रेन के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2024 के दौरान तोशाम ब्लॉक का कोई भी गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि, वर्ष 2025 के दौरान 9 सितंबर 2025 तक, 10 गांवों में 3,525 एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई थी, जिसमें 2 से 2.5 फीट तक जलभराव था।

सिंचाई विभाग के निरंतर प्रयासों से, बाढ़ के पानी को प्रभावित क्षेत्रों से काफी हद तक हटा दिया गया है, और 12 दिसम्बर, 2025 तक तीन गांवों में केवल 65 एकड़ जिसमे गांव रिवासा में 05 एकड़, गांव डांग कलां में 20 एकड़ और गांव सांगबान में 40 एकड़ भूमि प्रभावित रही। शेष 65 एकड़ से बाढ़ का पानी भी पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान गांव दांग कलां, भानगढ़, मानसरवास, सिमलीवास, लेघां भानान, लोहानी, ढाणी शंकर, लहलहाना, गोलागढ़, आसलबास, जुई खुर्द आदि में बाढ़ से संबंधित कार्यों पर 19.05 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, गांव जुई कलां, जुई बिचली, चंदावास, द्वागर, द्वाब ढाणी, बिजलानावास, केरू, खापरवास, बापोरा तथा आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित कार्यों पर 36.85 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। इस दौरान लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि 2155.90 करोड़ की लागत से संबंधित 61 कार्यों में से 42 विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

हरियाणा में आयोजित चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ विवादों का निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में एक परिवार फिर से जुड़ा, 18 सालों से अधिक के वैवाहिक विवाद का हुआ सौहार्दपूर्ण निपटारा

चंडीगढ़, । हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं हालसा की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति लिसा गिल के मार्गदर्शन में वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 जिलों और 35 उपमंडलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आयोजित की गई। आज की लोक अदालत में, पूर्व-लोक अदालत बैठकों सहित कुल 5,53,741 मामलों का निपटारा हुआ, जो सुलभ और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए हालसा और न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्यस्थता के माध्यम से एक संतोषजनक परिणाम सामने आया, जिसमें 18 वर्षों से अधिक के अलगाव के बाद एक पति-पत्नी का पुनर्मिलन हुआ और एक लंबे वैवाहिक विवाद का सौहार्दपूर्ण और गरिमापूर्ण समाधान हुआ। इनका विवाह 4 दिसंबर 2001 को हुआ था। वैवाहिक कलह के कारण, यह दंपति 5 जुलाई 2008 को अलग हो गए थे। वर्षों से सुलह के कई प्रयासों के बावजूद, विवाद अनसुलझा रहा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मुकदमा दायर करना पड़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठासीन अधिकारी-एवं-अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पूनम कंवर, परिवार न्यायालय, गुरुग्राम और कानूनी सहायता सदस्य अलरीना सेनापति की अध्यक्षता में आयोजित मध्यस्थता सत्र के दौरान, दोनों पक्षों ने रचनात्मक संवाद किया। प्रभावी मध्यस्थता के परिणामस्वरूप, उनके बीच सभी विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गए और वे अपने वैवाहिक जीवन को पुनः आरंभ करने के लिए सहमत हो गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुरुक्षेत्र परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री विवेक सिंघल द्वारा एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित पांच साल पुराने अभिरक्षा विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया। अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम (जी.डब्ल्यू-24-2020) के तहत दायर याचिका, जिसमें दादी ने अपने नाबालिग पोते की अभिरक्षा की मांग की थी, न्यायालय द्वारा प्रभावी परामर्श और हस्तक्षेप के बाद सुलझाई गई। नाबालिग बच्चे, उसकी मां और दादी से बातचीत करने और बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए, पक्षों ने 12 दिसंबर 2025 को पूर्व-लोक अदालत में आपसी सहमति से समझौता किया। समझौते के अनुसार, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा मां के पास रहेगी, जबकि दादी को न्यायालय परिसर में मासिक मुलाकात का अधिकार दिया गया है। हरियाणा के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों एवं सचिवों तथा लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों के साथ 10 दिसंबर 2025 को आयोजित व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान, न्यायमूर्ति लिसा गिल ने प्रभावी मुकदमों के निपटारे के लिए निष्ठापूर्वक, समन्वित और सक्रिय प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों को शीघ्र, निष्पक्ष और पारस्परिक सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग करने का आग्रह किया था। न्यायमूर्ति गिल ने लोक अदालत की पीठों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए अपनी उच्चतम स्तर की प्रतिबद्धता और दक्षता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे सभी के लिए सुलभ और किफायती न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-सदस्य सचिव जगदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्यभर में आयोजित लोक अदालतों के कामकाज की बारीकी से निगरानी की। उन्होंने पंचकुला के जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालत पीठों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और पक्षकारों से बातचीत करते हुए लोक अदालत पीठों की कार्यवाही की समीक्षा की। विभिन्न न्यायालयों में वाद पूर्व और लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कुल 192 पीठों का गठन किया गया था।

हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धराः नायब सिंह सैनी

सांसद खेल महोत्सव युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह महोत्सव 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन-आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेलों को जन-आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता यह महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्टीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद में %सांसद खेल महोत्सव% के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को आयोजक राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में शामिल हो रहे खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट भी किया।

मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलों का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा तथा खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौंसला अफ़जाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45 हजार खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3604 खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे।

खिलाड़ियों व उपस्थितजन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि %सांसद खेल महोत्सव% से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप-10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा करवाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसलिए, खेल में हार-जीत से ज्यादा मेहनत, अनुशासन और लगन महत्वपूर्ण है। यही वे गुण हैं, जो युवाओं को भविष्य में एक बेहतर नागरिक और एक सफल खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे हों या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा कर रहे होते हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा है। प्रदेश का किसान देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देता है। जवान गर्मी-सर्दी की परवाह न करते हुए सरहदों पर डटा रहता है। इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अन्तर्राष्टीय खेलों में सोना जीतकर देश की झोली भरने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय-समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेण्डर भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार खेल महाकुम्भ, राज्यस्तरीय अखाड़ा दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीवाल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, बास्केट बॉल, हैंड बाल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे, जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए।

हर बिरादरी का सम्मान और उत्थान सुनिश्चित कर रही नायब सरकारः डॉ. अरविंद शर्मा

गरीब की पूंजी उसके बच्चे, बेहतर शिक्षा देने पर करें फोकस

चंडीगढ़, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार के साथ काम करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सरकार हर बिरादरी का सम्मान और उत्थान सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विचार को धरातल पर उतार रही है।

डॉ. अरविंद शर्मा आज गोहाना के उत्तम नगर स्थित श्री सैन भगत धर्मशाला परगना 52 के 42वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सभी बिरादरी का सम्मान करते हैं और उनके उत्थान के लिए निरंतर जनहित की योजनाएं लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार संत-महापुरूषों की जयंतियों का राज्य स्तर पर आयोजन करते हुए उनके विचार जन-जन तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने सैन समाज से आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है, अपितु उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ गत दिनों मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत से किया था।सरकार हर विधानसभा स्तर पर अंत्योदय मेलों का आयोजन करते हुए गरीब परिवारों को स्वरोजगार एवं आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए अवसर दे रही है, जिसका आमजन को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब की पूंजी उसके बच्चे होते हैं, ऐसे में बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने सैन भगत धर्मशाला में विकास कार्यों के लिए स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने धर्मशाला में लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए भी पांच लाख रुपए देने की घोषणा की।

ओल्ड फरीदाबाद के समग्र विकास का रोडमैप तैयारः विपुल गोयल

चंडीगढ़, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि ओल्ड फरीदाबाद केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि उनका घर है, जहां की गलियों में खेलते हुए, बुजुर्गों की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा। ऐसे में इस क्षेत्र के विकास के प्रति उनका दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। श्री विपुल गोयल शनिवार को फरीदाबाद में महार्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन पुनः निर्माण एवं बस्सा पाड़ा में आरएमसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ करने उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज वाल्मीकि मंदिर परिसर में लंबे समय से लंबित सामुदायिक भवन जिस पर लगभग 52.5 लाख रुपये की लागत से निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार उसे भी उपलब्ध कराएगी, ताकि क्षेत्रवासियों को एक आधुनिक और उपयोगी सामुदायिक भवन मिल सके। इसके साथ ही ओल्ड फरीदाबाद की विभिन्न गलियों के पक्कीकरण कार्य की भी शुरुआत की गई। इन कार्यों में 18.5 लाख रुपये और 22.5 लाख रुपये की लागत से दो प्रमुख गली विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ओल्ड फरीदाबाद के लिए आने वाला एक वर्ष विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे अनाज मंडी क्षेत्र में नए अस्पताल की योजना हो, नए स्कूलों की स्थापना हो, पानी-बिजली की बेहतर व्यवस्था हो या जहां-जहां कच्ची सड़कें हैं, उन्हें पक्का करने का कार्य—इन सभी मोर्चों पर सरकार तेजी से काम करेगी। उन्होंने ओल्ड फरीदाबाद के ऐतिहासिक बराही तालाब के पुनरुद्धार की भी महत्वपूर्ण घोषणा की। श्री गोयल ने बताया कि क्षेत्र में पार्कों की संख्या सीमित है, इसलिए मौजूदा पार्कों को और अधिक सुंदर व उपयोगी बनाया जाएगा। नई सब्जी मंडी में बनाई गई पार्किंग सुविधा को भी अगले एक-दो महीनों में शुरू किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकेगी।

मार्च-2026 तक एम्स में शुरू हो जाएगी ओपीडी -राव इंद्रजीत सिंह

चंडीगढ़, केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन एवं योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को गांव माजरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का निरीक्षण कर जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने दी गई गाइडलाइन के तहत मार्च-2026 तक एम्स में ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने एम्स और एजेंसी के अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि रेवाड़ी जिला के माजरा गांव में बन रहे एम्स को अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा किया जाए और ओपीडी शुरू होने से रेवाड़ी जिले व आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ बाकी कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा फैकल्टी संबंधी व्यवस्थाएं भी समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मेडिकल क्लासेज भी अगले सेशन में शुरू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन के ऊपर से बनने वाले ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए।

कांग्रेस के झूठ के खिलाफ हरियाणा भाजपा का संगठित अभियान, जन-जन तक पहुंचेगा अमित शाह का संदेश

चंडीगढ़, । लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस के झूठ और भ्रम की राजनीति को तथ्यों के साथ उजागर किए जाने के बाद हरियाणा भाजपा ने इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय ÷मंगल कमल÷ में भाजपा की प्रदेश मीडिया टीम और प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा भाषण के प्रमुख अंश स्क्रीन पर दिखाए गए। प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने सभी प्रवक्ताओं एवं पदाधिकारियों के समक्ष आगे की कार्य योजना प्रस्तुत की। संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल ने एसआईआर और ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करने का आह्वान किया। प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने स्वयं 11 बार एसआईआर कराया, फिर अब उसी प्रक्रिया का विरोध करना कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव जीते, तब कोई सवाल नहीं उठाया गया। वर्ष 2014 से 2025 के बीच हुए 71 विधानसभा चुनावों में से 30 में विपक्ष की जीत यह साबित करती है कि ईवीएम पर आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

उन्होंने सवाल किया कि यदि बिहार में एसआईआर और ईवीएम को लेकर विपक्ष को आपत्ति है तो अब तक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई गई, जबकि अभी भी 45 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई है। विपक्ष में हिम्मत है तो अभी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दे सकते है, लेकिन कांग्रेस को पता है उसके आरोप निराधार और झूठे हैं, इसलिए वो केवल भ्रम की राजनीति कर रही है। अरविंद सैनी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर वीडियो डिलिट करने का आरोप लगाती है, जबकि सच्चाई यह है कि 45 दिनों के बाद कोई भी चुनावी प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता, ऐसे में 45 दिन के बाद वीडियो रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।

अरविंद सैनी ने कहा कि लोकसभा में जब गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस के हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दे रहे थे, तब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस संसद छोड़कर बाहर चली गई, जिससे साफ है कि कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती और केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है।

संपादकीय

एम्स में खुलासा अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी ले रहे हैं नशा

बच्चों में आमतौर पर नई चीजों को जानने-समझने और परखने की जिज्ञासा होती है। ऐसे में अगर वे नशे का सेवन करने वाले किसी साथी या अन्य व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो उन्हें भी यह लत लगने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा मानसिक दबाव और तनाव भी बच्चों को नशे के जाल में धकेल सकता है। देश भर में हाल में किए गए एक अध्ययन में इन पहलुओं को उजागर किया गया है। दिल्ली एम्स के शोधकर्ताओं ने कुछ अन्य शोधार्थियों के साथ मिलकर यह अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि स्कूली छात्रों के बारह साल या इससे कम उम्र में ही नशे की जद में आने का जोखिम बना रहता है। इसका मुख्य कारण आज के दौर में बच्चों का नशीले पदार्थों तक आसानी से पहुंच है। सवाल है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? शहर से लेकर गांव तक नशे का जो काला कारोबार फैल रहा है, उसे रोकने के प्रयास जमीनी स्तर पर कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रहे हैं?दरअसल, एम्स का यह अध्ययन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बंगलुरु और हैदराबाद समेत देश के दस शहरों एवं उनके आसपास के ग्रामीण इलाकों में किया गया। इसमें सरकारी और निजी स्कूली के छात्रों को शामिल किया गया। इस दौरान पंद्रह फीसद छात्रों ने कम से कम एक बार नशीले पदार्थों का सेवन करने की बात स्वीकार की, जबकि दस फीसद ने पिछले एक वर्ष में मादक पदार्थ लेने की बात कही। इससे पता चलता है कि बारह वर्ष या उससे कम उम्र में भी बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं।अध्ययन के दौरान एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी सामने आया कि कई बार बच्चे पारिवारिक कलह से उपजे तनाव को कम करने के लिए भी नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए पारिवारिक माहौल का स्वस्थ होना कितना जरूरी है। अभिभावकों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के साथ नियमित संवाद करें तथा उन्हें सही और गलत का बोध कराएं।

नेपाल ने फिर छेड़ा काली का राग

नेपाल ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दर्शाने वाले मानचित्र के साथ अपना 100 रुपये का नया करेंसी नोट जारी कर भारत के साथ दो सदी से भी पुराने सीमा विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। मई 2020 में के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने भी एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का क्षेत्र दिखाया गया था। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच नयी दिल्ली में गत 18 अगस्त को हुयी वार्ता में आपसी व्यापार के लिये जिन तीन नये रास्ते खोलने पर सहमति बनी है उनमें से एक लिपुलेख भी है जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई है।

(जयसिंह रावत)

जिस कूटी यांग्ती नदी को नेपाल काली बता रहा है वह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जिसमें दो किनारों की विभाजक दिशाएं पूरब पश्चिम नहीं बल्कि उत्तर -दक्षिण हैं। इस कूटी घाटी के निचले आबादी वाले क्षेत्र में नदी के दोनों ओर भारत और नेपाल के गांव हैं। जबकि, भारत जिस नदी को काली मानता है वह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसलिये संधि के हिसाब से पूरब में नेपाल के दार्चुला जिले के छांगरू, दिलीगाड़, तिंकर और कौआ गांव हैं, जबकि पश्चिम में भारत की गुंजी, नपलच्यू, रौंगकौंग, नाबी, कूटी, गर्ब्यांग और बुदी ग्राम सभाएं हैं।

उत्तराखण्ड में मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके नृपसिंह नपलच्याल का गांव इसी क्षेत्र के नपलच्यू में है। गुंजी, नाभी और कूटी के एक दर्जन से अधिक आइएएस, आइपीएस, पीपीएस और पीसीएस अधिकारी उत्तराखण्ड और भारत सरकार की सेवा में हैं।

यह विवाद नया नहीं है जिसे नेपाल पिठले 208 वर्षों से यदाकदा उठाता रहा हैं। भारत जिस नदी को काली नदी मानता है, नेपाल उसकी जगह कूटी यांग्ती को असली काली नदी बताता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 2 दिसम्बर 1815 को सम्पन्न हुयी सुगोली की संधि में काली नदी को ही भारत और नेपाल के बीच विभाजन रेखा माना गया है।

नेपाल की नवीनतम आपत्ति इस बात को लेकर है कि दोनों देशों ने लिपुलेख से व्यापार खोलने पर संधि कर ली जबकि काली नदी की उसकी अपनी परिभाषा के अनुसार यह क्षेत्र

नेपाल का भू भाग है।

भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुयी सहमति के परिणाम स्वरूप भारत की ओर से लिपुलेख, शिप्की लॉ और नाथू लॉ से प्राचीन व्यापारिक मार्ग खुलने हैं। लेकिन इस सहमति के बाद नेपाल ने अड़ंगा खड़ा करने के लिये एक बाद फिर नये नोट पर विवादित मानचित्र छाप कर पुराने विवाद को हवा दे दी।

भारत के लिये लिपुलेख दर्रा आर्थिक, सामरिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व का है। यहीं से चीन के साथ व्यापार शुरू होने के साथ ही यही कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी है। यही वह दर्रा है जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान सबसे मजबूत मोर्चा साबित हुआ था। इसलिये तभी से यहां पर भारत की सुरक्षा चौकियां स्थापित हैं।

हालांकि, नेपाल का यह सपना कभी साकार होने वाला नहीं है फिर भी नेपाल में भारत विरोधी तत्व सदैव काली नदी के विवाद को दोनों देशों के बीच तनातनी का मुद्दा बनाये रखेंगे। चीन भी ऐसे तत्वों को हवा देता रहेगा।

सुगोली में 2 दिसम्बर 1815 को नेपाल के महाराजा विक्रमशाह बहादुर शमशेर जंग के प्रतिनिधि राजगुरू गजराज मिश्र और चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कंपनी की ओर से ले0 कर्नल ब्रैडशॉ ने जिस संधि पर हस्ताक्षर किये थे, उसमें सतलज से लेकर घाघरा और मेची के बीच का सारा भूभाग अंग्रेजों के अधीन मान लिया गया था।

नेपाल इस संधि को तो मानता है, लेकिन वह कालापानी से 16 किमी दूर लिम्पिया धुरा से निकलने वाली उस नदी को काली नदी मानता है जिसे भारत कूटी यांग्ती मानता रहा हैं।

अगर नेपाल का दावा मान लिया जाए तो न केवल लिपुलेख दर्रा और कालापानी अपितु उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की 7 ग्राम सभाएं भी नेपाल में चली जाती हैं। सुगोली की संधि की धारा 5 में साफ लिखा गया है कि काली नदी के पश्चिम वाला हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिक्षेत्र होगा और उस क्षेत्र पर तथा क्षेत्र वासियों पर नेपाल का राजा या उसके उत्तराधिकारी कभी दावा नहीं करेंगे।

इन दोनों जलधाराओं का गुंजी के निकट मनीला में संगम होता है। तवाघाट में काली नदी में धौली, जौलजीवी में गोरी, पीपली में चरमा और पंचेश्वर में सरयू नदियां मिलती हैं। टनकपुर से काली नदी शरदा और लखीमपुर से घाघरा हो जाती है।

दरअसल, सुगोली की संधि के बाद से ही नेपाल अंग्रेजों से ही काली नदी को लेकर विवाद करने लग गया। कारण यह कि संधि के समय उस क्षेत्र का कोई नक्शा ही नहीं था।

वह क्षेत्र इतना दुर्गम था कि उस समय के शासकों के लिये उससे राजस्व की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हिमालयन गजेटियर (सन् 1884= वाल्यूम-2 पार्ट-2= 679-680) में ई.टी. एटकिन्सन लिखता है कि संधि के अनुसार टौंस से शारदा तक पूरा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया, मगर उत्तर में केवल एक छोटे तथा महत्वहीन क्षेत्र पर विवाद बना रहा।

इसके साथ ही संधि के अनुसार ब्यांस परगना के दो हिस्से हो गये थे, जबकि अब तक वह कुमाऊं का अभिन्न हिस्सा था। वैसे भी यह जुमला और डोटी से अलग क्षेत्र था।

नेपाल ने कुमाऊं के कमिश्नर और नेपाल के रेजिडेंट ई0 गार्डनर को 4 फरबरी 1817 को परगना ब्यांस में काली के पूर्व में पड़ने वाले तिंकर और छांगरू गावों पर अपना दावा पेश करते हुये पत्र लिखा तो वे सचमुच काली नदी के पूरब में थे, इसलिये उन्हें डोटी के तत्कालीन सूबेदार बमशाह के अधिकार में दे दिया गया। इससे भी नेपाल सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने कूटी तथा नाभी की भी मांग करनी शुरू कर दी।

इस पर नेपाल के रेजिडेंट एवं कुमाऊं कमिश्नर ने कैप्टन वेब से नेपाल के दावे की जांच कराई तो उसने सन् 1818 तक कुमाऊं का व्यापक दौरा किया। 11अगस्त और 20 अगस्त 1817 को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में वेब ने माना कि पवित्र कालापानी चश्मे से निकलने वाली, मगर कम पानी वाली जलधारा ही सदैव काली की मुख्य शाखा मानी जाती रही है। काला पानी के कारण ही उसका नाम काली रखा गया। इस नदी का काली नाम तब तक रहता है जब तक वह पहाड़ों में बहती है और मैदान में उतरने पर वह शारदा नदी हो जाती है। इसलिये ब्रिटिश सरकार ने नेपाल का दावा खारिज कर नाभी और कूटी गावों को अपने पास ही रखने का निर्णय लिया और तब से ये गांव ब्रिटिश ब्यांस के ही हिस्से रहे। ब्यांस घाटी के ये सभी गांव रं भोटिया जनजाति के हैं। यह लेखक के निजी विचार हैं।

प्रशासनिक तंत्र की तय हो जवाबदेही..

(उमेश चतुर्वेदी)

दुर्घटनाएं कह कर नहीं आतीं, लेकिन उनकी रोकथाम की मुकम्मल तैयारी से शायद ही किसी को इनकार हो। लेकिन समंदर के किनारे से छनकर आती रोशनियों के बीच स्थित गोवा के इस नाइट क्लब में लगी आग और उसमें गई निर्दोष जान ने सबसे बड़ा सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर लगाया है, जिस पर इस हादसे की रोकथाम की जिम्मेदारी थी।उत्तर भारत की सर्दियां गोवा के लिए वरदान होती हैं। अरब सागर तटीय इस राज्य में सर्दियों में उत्तर भारतीय सैलानियों की आवक बढ़ जाती है। लेकिन हो सकता है कि इस बार यह आवक कम हो। गोवा में साल के आखिरी दिनों और अगले साल की छुट्टियां मनाने का मन बना चुके सैलानियों में इस बार हिचक हो सकती है। वजह है, यहां के मशहूर नाइट क्लब 'बर्क बाय रोमियो लेन' में लगी आग, जिसमें पांच सैलानी समेत पच्चीस लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटनाएं कह कर नहीं आतीं, लेकिन उनकी रोकथाम की मुकम्मल तैयारी से शायद ही किसी को इनकार हो। लेकिन समंदर के किनारे से छनकर आती रोशनियों के बीच स्थित गोवा के इस नाइट क्लब में लगी आग और उसमें गई निर्दोष जान ने सबसे बड़ा सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर लगाया है, जिस पर इस हादसे की रोकथाम की जिम्मेदारी थी। बताया जा रहा है कि अनधिकृत ढंग से इस नाइट क्लब का निर्माण किया गया था। इस अनधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिए गोवा की संबंधित पंचायत ने निर्देश भी दे रखा है। आग लगने की दशा में उसके रोकथाम और बचाव को लेकर इस नाइट क्लब में कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, यह क्लब बेहद संकरी जगह पर है, जहां आसानी से जाना संभव नहीं है। भारत में एक चलन स्वीकार कर लिया गया है। नियमावलियां तो खूब बनाई गई हैं। लेकिन वे सिर्फ दस्तावेजों के लिए हैं। जिन्हें इन नियमावलियों को लागू करने की जिम्मेदारी है, जिन पर इन नियमावलियों को तोड़ने वालों को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित करने-कराने की जवाबदेही है, अक्सर वे इससे आंखें मूंद लेते हैं। कई बार नियम तोड़ने वालों से संबंध पलकों को मोड़ने का जरिया बनते हैं तो कई बार रिश्वत की रकम का बोझ पलकों को झुकने के लिए मजूबूर कर देता है। भारत के प्रशासनिक तंत्र का बड़ा हिस्सा इसी तरह की मानसिकता में काम करता है। वह दुर्घटनाओं और हादसों का इंतजार करता है। वह तभी जागता है, जब हादसे हो जाते हैं, उनमें मासूम जानें चली जाती हैं। तब उन्हें नियमों की तेजी से याद आने लगती है। प्रशासनिक तंत्र की बंद आंखे तब ऐसे खुल जाती हैं, जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। तब उसे अनधिकृत निर्माण भी दिखने लगता है, तब उसे कार्रवाई की भी सूझने लगती है। कार्रवाई होती भी है। गोवा के 'बर्क बाय रोमियो लेन' क्लब के मालिकों पर भी होगी, लेकिन इसका असर कितनी देर तक रहेगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि वक्त बीतते-बीतते कार्रवाई में ढिलाई भी शुरू हो सकती है और अगर किसी सामाजिक संस्था, किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी न्यायिक व्यवस्था की निगाह उस पर नहीं पड़ी तो कार्रवाई धीरे-धीरे टलती चली जाएगी, उसकी तासीर ठंडी होती जाएगी और फिर हो सकता है कि नियमों को तोड़ने वाले किसी और जगह नियम तोड़कर ऐसा ही किसी और नाम से नाइट क्लब चलाने लगें भारत में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचा अपने राजकाज को चलाने के लिए बनाया था। उसे लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए बनाया था। देखते ही देखते यह तंत्र स्टील फ्रेम में तब्दील होता चला गया। वैसे भी जर्मन दार्शनिक मैक्स वेबर इसे स्टील फ्रेम ही बताते हैं। संविधान सभा ने भारत के भावी प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा को लेकर चर्चा की थी। उसने इस पर गंभीर विमर्श किया था। संविधान सभा में प्रशासनिक तंत्र पर व्यापक चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो स्वतंत्र भारत के लिए प्रभावी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह हो । संविधान सभा के सदस्यों को संदेह था कि भारत की भावी नौकरशाही भारतीय मूल्यों और भारतीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं हो पाएगी। इसी लिए संविधान सभा में तत्कालीन सदस्यों ने नौकरशाही की भूमिका पर ना सिर्फ व्यापक चर्चा की, बल्कि उसकी राजनीतिक तटस्थता, कार्यक्षमता, जवाबदेही और नए स्वतंत्र राष्ट के लोकतांत्रिक ढांचे में उसकी स्थिति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया । इन बहसों का उद्देश्य एक ऐसी सिविल सेवा प्रणाली स्थापित करना रहा, जो संविधान के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान हो और लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो। सवाल यह है कि क्या संविधान सभा की बहसों के अनुरूप आज की नौकरशाही बन पाई है। उसके ज्यादातर हिस्सों को देखिए तो लगता है कि बिल्कुल नहीं। आज भी उसमें अंग्रेजी राज जैसी अकड़ है, उसका ध्यान ज्यादातर अपनी ताकत को बचाए रखने और उसके जरिए आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने पर है। भारत का शायद ही कोई राज्य हो, जहां की नौकरशाही में अकूत संपत्ति के मालिक, भ्रष्टाचारी और कर्त्तव्यहीन अफसर ना होंगे। मध्य प्रदेश जैसे जिन राज्यों में लोकपाल व्यवस्था कायम है, वहां आए दिन ऐसे अफसरों पर छापे पड़ते हैं, उनके घर मिले नोटों को गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ती हैं। कई बार तो नोट गिनने में ही दो-दो तीन-तीन दिन लग जाते हैं। सवाल यह है कि क्या अफसरों के पास अकूत धन उनके सत्कर्मों और कर्त्तव्यपरायाणता के चलते आता है? निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब ना में हैं। पैसे आते हैं, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने से, नियमों की अवहेलना करने वालों से मिलने वाली रकम से, लोक के लिए आए फंड की बंदरबांट से। बिना प्रशासनिक मिलीभगत के यह कल्पना बेकार है कि किसी नाइट क्लब में अवैध निर्माण होगा, वह संकरी गलियों में चलेगा और उसमें सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी होंगे। आज जरूरत इस बात की है कि अब हर गलत कार्य के लिए, गलत कार्य करने वाले, नियम तोड़ने वाले, कानून का उल्लंघन करने वाले को दोषी ठहराने की न्यायिक प्रक्रिया तो चले ही, साथ ही उसके लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहे अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाए, उन्हें खोजकर उचित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के जरिए दंडित किया जाए। सड़कों पर अव्यवस्था फैली रहेगी, नियमों की अनदेखी से अराजकता बनी रहेगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या इस तरीके से सोचने को हमारा राजनीतिक ढांचा तैयार है? लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

वर्ग पहेली 5942

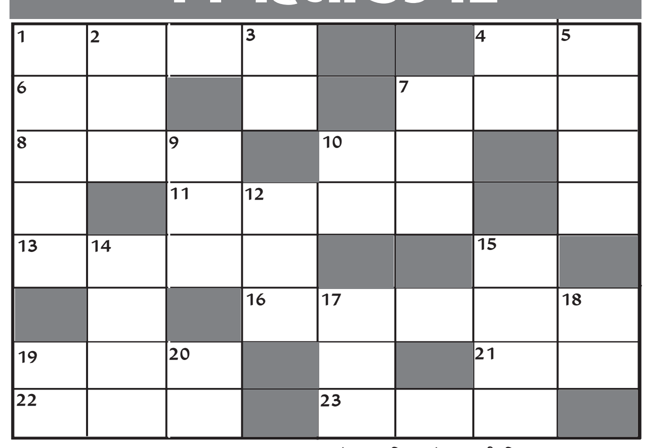

संकेत: बाएं से दाएं
1. अनंत आकाश, उच्चाकाश (4)
5. इश्क, प्रेम (2)
6. देह की वह भाग सिर को धड़ से जोड़ता है, कंठस्वर (2)
7. कयास, अनुमान, अटकल (3)
8. क्षेत्रफलन, को यह भी कहते है (3)
10. संलग्न होने वाला, जो लगने योग्य हो (2)
11. पशु, प्राणी जो चौपाएं हों, जीवधारी (4)
13. व्यायाम, वर्जिश, ड्रिल, शरीर को बनाने की क्रिया (4)
16. नमक रखने का पात्र (5)
19. नाम धारण करने वाला, नामयुक्त, संज्ञावान (3)
21. मूल्य, कीमत, मोल (2)
22. लिखने वाला, लेखक, क्लर्क, लिपिक (3)
23. बिना पकी भोजन सामग्री, संपूर्ति (3)

ऊपर से नीचे
1. बॉडीगार्ड, शरीर की रक्षा करने वाला (5)
2. पति-पत्नी का कानूनी रूप से संबंध विच्छेद (3)
3. माफी, दक्ष की ग्यारह पुत्रियों में से एक, दंडमुक्ति (2)
4. शतरंज का सबसे छोटा मोहरा (2)
5. चंद्रमा, शशि, मयंक, रजनीपति (4)
7. एक छोटा मीठा फल, गुलजार के निर्देशन में संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी, देवन वर्मा की हास्य फिल्म (1982)(3)
9. दरीबा, मार्के, शॉपिंग सेंटर (3)
10. चरसा खींचने का मोटा रस्सा, लौंग (2)
12. नमन, अभिनति, झुकान (3)
14. जो कही हुई बात मानने का तैयार हो (4)
15. खुदा का दिया हुआ (4)
17. मगर (3)
18. वृक्ष की इस छाल से औषधि निर्माण भी होता है (2)
19. किसी नगर या कस्बे का प्रवेश स्थल (2)
20. किसी समय, किस वक्त (2)

वर्ग पहेली 5941 का हल

मुं	ब	ई		का	मा	य	नी
ह	म	श	क्ल		र	ह	ल
दि		दू	ब		को		
खा	दि	त		ग	नी	म	त
ई	शा		मु	श्त		घा	न
	सू	ची			रे		
अ	च	ल		ति		आ	ज
	क		त	ल	ब	गा	र

भारत एक सनातन यात्रा है

(लव गौर)

आचार्य रजनीश ने कहा था कि भारत कोई भूखंड नहीं है। यह एक सनातन यात्रा है, एक अमृत पथ है, जो अनंत तक फैला हुआ है। मैं भी उस अनंत यात्रा का छोटा-मोटा यात्री हूं।

पृथ्वी के इस भूभाग में मनुष्य की चेतना ने पहली किरण के साथ उस सपने को देखना शुरू किया था। उस सपने की माला में कितने फूल पिरोए हैं, लाखों ऋषि, राम, कृष्ण, पतंजलि, अष्टावक्र कितने गौतम बुद्ध, कितने महावीर, कितने कबीर, रैदास, मीरा, राम-कृष्ण कितने नानक उस सपने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर गए। उस सपने को मैं अपना कैसे कहूं? वह सपना मनुष्य का, मनुष्य की अंतरात्मा का सपना है। उस सपने को हमने एक नाम दे रखा था। हम उस सपने को भारत कहते हैं। भारत कोई भूखंड नहीं है। न ही कोई राजनैतिक इकाई है, न ऐतिहासिक तथ्यों का कोई टुकड़ा है। न धन, न पद, न प्रतिष्ठा की पागल दौड़ है। भारत है एक अभीप्सा, एक प्यास-सत्य को पा लेने की। उस सत्य को, जो हमारी धड़कन-धड़कन में बसा है। उस सत्य को, जो हमारी चेतना की तहों में सोया है। वह, जो हमारा होकर भी हमसे भूल गया है। उसका पुनर्स्मरण, उसकी पुनःउद्घोषणा भारत है।

अमृतस्य पुत्रः! हे अमृत के पुत्रो। जिन्होंने इस उद्घोषणा को सुना, वे ही केवल भारत के नागरिक हैं। भारत में पैदा होने से कोई भारत का नागरिक नहीं हो सकता। जमीन पर कोई कहीं भी पैदा हो, किसी देश में, किसी सदी में, अतीत में या भविष्य में, अगर उसकी खोज अन्तस्थ की खोज है, तो ही वह भारत का निवासी है। मेरे लिए भारत और अध्यात्म एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसलिए भारत के पुत्र जमीन के कोने-कोने में हैं और जो संयोगवश केवल भारत में पैदा हो गए हैं, जब तक उन्हें अमृत की तलाश पागल न बना दे, तब तक वे भारत के नागरिक होने के अधिकारी नही हैं।

भारत एक सनातन यात्रा है, एक अमृत पथ है, जो अनंत से अनंत तक फैला हुआ है। इसलिए हमने कभी भारत का इतिहास नहीं लिखा। इतिहास भी कोई लिखने की बात है। साधारण-सी दो कौड़ी की रोजमर्रा की घटनाओं का नाम इतिहास है। जो आज तूफान की तरह उठती हैं और कल जिनका कोई निशान भी नहीं रह जाता। इतिहास तो धूल का बवंडर है। भारत ने इतिहास नहीं लिखा। भारत ने तो केवल उस चिरंतन की ही साधना की है, वैसे ही जैसे चकोर चांद को एकटक बिना पलक झपकाए देखता रहता है। मैं भी उस अनंत यात्रा का छोटा-मोटा यात्री हूं। चाहता था कि जो भूल गए हैं, उन्हें याद दिला दूं, जो सो गए हैं, उन्हें जगा दूं और भारत अपनी आंतरिक गरिमा व गौरव को, अपनी हिमाच्छादित ऊंचाइयों को पुनः पा ले, क्योंकि भारत के भाग्य के साथ पूरी मानवता की किस्मत जुड़ी हुई है। यह केवल किसी एक देश की बात नहीं है। अगर भारत अंधेरे में खो जाता है, तो आदमी का कोई भविष्य नहीं है और अगर हम भारत को पुनः उसके पंख दे देते हैं, पुनः उसका आकाश दे देते हैं, पुनः उसकी आंखों को सितारों की तरफ उड़ने की चाह से भर देते हैं, तो हम केवल उनको ही नहीं बचाते हैं, जिनके भीतर प्यास है। हम उन्हें भी बचा लेते हैं, जो आज सोए हैं, लेकिन कल जागेंगे, जो आज खोए हैं, लेकिन कल घर लौटेंगे। भारत का भाग्य मनुष्य की नियति है, क्योंकि हमने जैसे मनुष्य की चेतना को चमकाया था और हमने जैसे दीये उसके भीतर जलाए थे। जैसी सुगंध हमने उसमें बिखेरी थी, वैसी दुनिया में कोई भी नहीं कर सका था। यह कोई दस हजार साल पुरानी सतत साधना है, सतत योग है, सतत ध्यान है। हमने इसके लिए बाकी सब कुछ खो दिया।

आज का राशिफल

मेष
आज आप कोई महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं। इसके सफलतापूर्वक पूरा होने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। आर्थिक लाभ की संभावना बनती हुई दिख रही है। सेहत और वित्तीय मामलों की अनदेखी न करें। फिलहाल जमीन-जायदाद के लिए निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृष
आज के दिन थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई व्यक्ति आपके सामने कोई प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन उसके बहकावे में न आएं। सायंकाल से रात्रि तक किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। आज का दिन स्वास्थ्य के लिए खराब है। खान-पान से बचें। आलस्य का भी त्याग करें।

मिथुन
जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति होती आज के दिन दिख रही है। भाग्य आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी मिलेगी। भुगतान मिलने के बाद आपका व्यावसायिक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। उपयुक्त व्यक्ति और उम्दा अवसर आपको मिलते रहेंगे, जिनकी अतीत में आपको तलाश थी।

कर्क
आज सायंकाल के समय परिवार के सदस्यों और दोस्तों के प्रति आपका रवैया उदार रहेगा। आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। विलासिता पूर्ण माहौल का लुप्त उठाने का मौका मिलेगा। बड़ी मात्रा में पैसा हाथ में आने से आप संतुष्टि महसूस करेंगे। रात्रि में इन लोगों पर धन का खर्चा भी हो सकता है।

सिंह
आज पति-पत्नी के संबंध प्रेम पूर्ण और सहयोग पूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आप विभिन्न कार्यों में सक्रियता पूर्वक भाग लेंगे। अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप अपने संसाधनों को एकजुट करने में सफल रहेंगे। सायंकाल का समय अध्यात्म समागम में व्यतीत होगा। रात्रि में आपको कोई तोहफा या सरप्राइज मिल सकता है।

कन्या
आज सहकर्मियों के सहयोग से आप एक परियोजना को पूरा करने में सफल रहेंगे। किसी महान व्यक्ति के हस्तक्षेप से पारिवारिक विवाद का समाधान हो जाएगा। आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। परिस्थितियों का आकलन करें और फिर दिल और दिमाग की बात सुनकर फैसला लें।

तुला
आज आपको त्रिकोणीय व्यापारिक साझेदारी व संबंधों से लाभ होगा, लेकिन निजी संबंधों के मामले में त्रिकोणीय रिश्ते आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आप जीवन में तीन भूमिकाएं निभाएंगे। बेहतर यही होगी कि हर भूमिका को अलग-अलग रखें, उन्हें आपस में मिलाएं नहीं, अन्यथा आप संशयग्रस्त हो जाएंगे।

वृश्चिक
आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होने के बावजूद आप जो भी कार्य साहस के साथ करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र और परिवार में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इनका सामना आप साहस के साथ करेंगे और विजेता बनकर उभरेंगे।

धनु
आज सेहत और वित्तीय संसाधनों पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे लोगों के कार्यों के लिए ज्यादा वक्त और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि ऐसे लोग एक के बाद एक दूसरी फरमाइश पेश करेंगे। आज समाज में भी आपका महत्व बढ़ेगा। मूड में उतार-चढ़ाव पर नजर रखें।

मकर
आज आप परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़े हैं। किसी कठिन दौर से गुज़र सकते है। लेकिन याद रखें, जब अंधेरा गहराता है तब सवेरा करीब होता है। सच्चाई का सामना करेंगे और आपके समक्ष भावनात्मक समस्याएं भी आएंगी।

कुंभ
आज निजी संबंधों पर भावनाएं हावी रहेंगी। अंतर्मन की पुकार को सुनें। हर मामले में अतिवादी से बचें। जीवन के कड़वे अनुभवों से सबक सीखें। अतीत को भूलकर वर्तमान में कदम आगे बढ़ाएं। आज आपके कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव की संभावना है।

मीन
आज आपने जो उम्मीदें संजो रखी हैं, उनके पूरा न होने पर आप खिन्न रहेंगे। निजी संबंधों के कुछ मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक बात आज विशेष रूप से नोट कर लें कि जीवन में जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तब आपके पारिवारिक सदस्यों से वांछित सहयोग कभी प्राप्त नहीं होगा।

धरा रह गया ट्रंप का टैरिफ, चीन ने मचाया तहलका

पहले कभी नहीं हुआ ऐसा... भारत के लिए बड़ी सीख

नई दिल्ली, एजेंसी।
चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। यानी चीन का एक्सपोर्ट उसके इम्पोर्ट से 1 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा है। इस साल के पहले 11 महीनों के दौरान चीन ने 3.4 ट्रिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया जबकि आयात थोड़ा घटकर 2.3 ट्रिलियन डॉलर रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में चीन और भारत की इकॉनमी और प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी। लेकिन आज चीन की इकॉनमी का साइज भारत से लगभग चार गुना है जबकि प्रति व्यक्ति आय भी कई गुना बढ़ चुकी है। चीन दो दशक से अधिक समय से दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। दुनिया के बाजार चीनी माल से पटे हुए हैं। आखिर कैसे हुआ यह चमत्कार?

चीन का चौंका देने वाला 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस दशकों की औद्योगिक नीतियों का परिणाम है। इसने चीन को 1970 के दशक में एक निम्न-आय वाले कृषि समाज से आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम बनाया है। चीन ने 1980 के दशक में टी-शर्ट और जूते जैसे कम लागत वाले निर्मित सामानों के एक भरोसेमंद उत्पादक के रूप में खुद को स्थापित किया। तब से यह औद्योगिक सीढ़ी पर चढ़कर इलेक्ट्रिक वाहन और सौर पैनल जैसे उच्च-मूल्य वाले सामानों तक पहुंच गया है।

अमेरिका के राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी टैरिफ लगाने के बावजूद चीन से विदेशों में माल की शिपमेंट खूब बढ़ी है। अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में ज्यादातर देशों पर भारी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, ताकि अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जा सके। लेकिन चीन ने दूसरे बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाकर दिखा दिया कि चीन, जिसे शुरुआत में 145 प्रतिशत तक अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में व्यापार वार्ता के लिए उन्हें कम कर दिया गया, इस टकराव से काफी हद तक बचा रहा है। उसने अमेरिका के बाहर के बाजारों में अपनी शिपमेंट बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि वह अमेरिका पर निर्भर नहीं है। नवंबर में इसमें फिर तेजी आई। इस दौरान उसका निर्यात एक साल पहले की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक रहा जबकि आयात में केवल 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2025 के पहले 11 महीनों के दौरान चीन का गुड्स सरप्लस पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 21.7 प्रतिशत बढ़ा। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा हाई-टेक सामानों की मजबूत मांग से आया, जो कुल निर्यात वृद्धि से 5.4 प्रतिशत अधिक था।

1 से 80 तक का सफर

चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हर क्षेत्र में भारी प्रगति की है और उसके साल 2075 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का अनुमान है। माना जा रहा है कि चीन की इकॉनमी तब 57 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी जबकि भारत 52.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर होगा। अभी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका 51.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर खिसक जाएगा।

एक दिन में 73 प्रतिशत भरा आईपीओ, ग्रे मार्केट दिखा रहा 255 का फायदा

ICICI Prudential AMC IPO GMP

नई दिल्ली, एजेंसी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को लेकर डबल खुशखबरी आई है। पहले दिन इस आईपीओ को जहां 73 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। वहीं, ग्रे मार्केट में आईपीओ ने लम्बी छलांग लगाई है। जिसकी वजह से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का जीएमपी 250 रुपये के स्तर को पार कर गया है। अभी यह आईपीओ अगले हफ्ते मंगलवार यानी 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। बता दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ 12 दिसंबर को खुला था। इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ का जीएमपी आज शनिवार को 255 रुपये है। आज का जीएमपी आईपीओ की 2400 रुपये के पार लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। 11 दिसंबर के मुकाबले जीएमपी में 105 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। बता दें, आज 13 दिसंबर को आईपीओ ग्रे मार्केट में अपने सबसे मजबूत स्थिति में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को ओपनिंग दिन में 73 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.21 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 1.97 गुना और एनआईआई में 0.38 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। बता दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ का साइज 10,602.65 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 4.90 करोड़ शेयर जारी करेगी। यह शेयर मौजूदा निवेशकों की तरफ से बेचा जा रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का प्राइस बैंड 2061 रुपये से 2165 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 6 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 12,990 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी। इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी।

6 दिन में 155 प्रतिशत चढ़ गया यह एसएमई स्टॉक

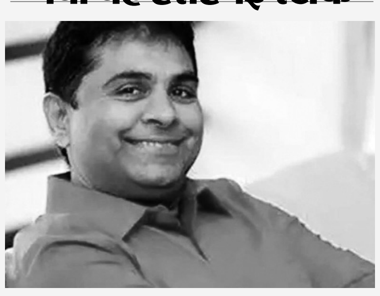

नई दिल्ली, एजेंसी। एसएमई स्टॉक एक्साटो टेक्नोलॉजीज में तूफानी तेजी जारी है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को क्व्स्थ में 5 पर्सेंट उछलकर 356.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज, शेयर बाजार में नई-नवेली कंपनी है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 दिसंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। 6 ट्रेडिंग सेशन में ही कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले 155 पर्सेंट उछल गए हैं। आईपीओ में एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 140 रुपये था। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी एक्साटो टेक्नोलॉजीज पर दांव है। दिग्गज इनवेस्टर विजय किशनलाल केडिया ने एसएमई कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज पर बड़ा दांव लगाया हुआ है। विजय केडिया के पास एक्साटो टेक्नोलॉजीज के 3,50,436 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 3.48 पर्सेंट है।

रिकॉर्ड बिक्री: पिछले महीने बिके 4.12 लाख से ज्यादा यात्री वाहन

जीएसटी कटौती से भी बिक्री को मिली रफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी।
त्योहारों के बाद भी मजबूत मांग बने रहने से देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री नवंबर, 2025 में सालाना आधार पर 18.7 फीसदी बढ़कर 4,12,405 इकाई के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। बीते साल नवंबर में कुल 3,47,522 यात्री वाहन बिके थे। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने पिछले महीने कुल 1,70,971 यात्री वाहन बेचे। यह नवंबर, 2024 में बेचे गए 1,41,312 यात्री वाहनों से 21 फीसदी अधिक है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की थोक बिक्री 46,222 इकाई के मुकाबले 22 फीसदी बढ़कर 56,336 इकाई पहुंच गई। इस दौरान ह्यूंडई मोटर इंडिया ने 50,340 यात्री वाहन बेचे, जो सालाना आधार पर चार फीसदी अधिक है। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, त्योहारों के बाद भी मजबूत मांग बने रहने और सरकार के जीएसटी सुधारों के समर्थन से घरेलू मोटर वाहन उद्योग ने नवंबर में बिक्री की रफ्तार को बरकरार रखा। यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों ने नवंबर में अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की। उम्मीद है कि निरंतर सहायक नीतिगत सुधारों और बेहतर बाजार भावनाओं से यह वृद्धि 2026 में भी जारी रहेगी।

दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री भी नवंबर में 21 फीसदी बढ़कर 19,44,475 इकाई के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक साल पहले की समान अवधि में 16,04,749 दोपहिया वाहन बिके थे। स्कूटर की बिक्री 5,68,580 इकाई से 29 फीसदी की वृद्धि के साथ?7,35,753 इकाई पहुंच गई। मोटरसाइकिल बिक्री पिछले महीने 17.5 फीसदी बढ़कर 11,63,751 इकाई के स्तर पर पहुंच गई। मोपेड की बिक्री में सालाना आधार पर दो फीसदी की गिरावट रही और कुल 44,971 इकाई बिके।?तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 71,999 इकाई पहुंच गई।

यात्री, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्यात में पिछले महीने 96.3 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई।?इस दौरान यात्री वाहनों का निर्यात सालाना आधार पर 39.8 फीसदी बढ़कर 84,646 इकाई?पहुंच गया।

नए लेबर कोड्स से महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा?

नई दिल्ली, एजेंसी।
नए लेबर कोड्स से देश में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह बात अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन और कानून फर्म शार्दुल अमरचंद द्वारा जारी एक श्वेत पत्र में कही गई है।

ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग- हाउ द लेबर कोड्स बूस्ट वीमेंस पार्टिसिपेशन इन इंडियाज वर्कफोर्स शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नए लेबर कोड्स रोजगार को अधिक सुरक्षित, संरक्षित और सुलभ बनाकर महिलाओं के लिए कार्यस्थल के अवसरों का विस्तार कर सकती हैं।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

श्वेत पत्र के अनुसार, भारत का कानूनी ढांचा सामाजिक बदलाव के साथ विकसित हुआ है, जिसका असर महिला श्रम बल भागीदारी दर में स्पष्ट रूप से दिखता है। वर्ष 2017-18 में यह दर 23.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

नए लेबर कोड्स का असर सीमित न रहने की संभावना

श्वेत पत्र के अनुसार, नए लेबर कोड्स का एक प्रमुख असर यह हो सकता है कि वे केवल नए अवसर पैदा करने तक सीमित न रहकर, काम को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाएं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मातृत्व संरक्षण को मजबूत बनाए रखा गया है। इसके अनुसार पात्र महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता रहेगा, जबकि दत्तक और सरोगेसी माताओं के लिए 12 सप्ताह का अवकाश जारी रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नर्सिंग ब्रेक, चिकित्सकीय सहायता और गर्भावस्था व प्रसव से जुड़े दस्तावेजों की सरल प्रक्रिया जैसे प्रावधान महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दबाव को कम करने में मददगार हैं, जो अक्सर उन्हें स्थायी रूप से कार्यबल से बाहर होने के लिए मजबूर कर देते हैं। श्वेत पत्र ने कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज के विस्तार की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसे अब सभी उद्योगों और जिलों, यहां तक कि प्लांटेशन सेक्टर तक लागू किया गया है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना एक दूरदर्शी कदम बताया गया है। खासकर उन महिलाओं के लिए, जो देखभाल की जिम्मेदारियों के चलते लचीले काम पर निर्भर रहती हैं।

महिलाओं के हित में बने कानून

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रगति को महिलाओं के हित में बने कानूनों, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम, 2013, के साथ-साथ सरकारी पहलों जैसे मिशन शक्ति, नव्या और वाइज-किरण से भी मजबूती मिली है। भारत के रोजगार कानून ढांचे का आधुनिकीकरण करती हैं।

लार्जकैप पसंदीदा साधन, पांच साल में 22.4 प्रतिशत रिटर्न

नई दिल्ली, एजेंसी। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड निवेश का पसंदीदा साधन बनते जा रहे हैं। इस फंड ने पांच वर्षों में 22 फीसदी से ज्यादा फायदा दिया है। कई फंड हाउसों की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां यानी (एयूएम) भी 50,000 करोड़ के पार हैं। निप्पॉन इंडिया लार्जकैप हाल में इसमें शामिल हुआ है। इससे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल व एसबीआई का भी एयूएम 50,000 करोड़ के पार हो गया था। यह उपलब्धि इक्विटी फंडों में कम निवेश के बावजूद हासिल हुई है, जिसका मुख्य कारण हालिया बाजार तेजी के बाद मुनाफावसूली और त्योहारी सीजन में तरलता की बढ़ती जरूरतों का प्रभाव है। लार्ज कैप फंड नए व जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प माने जाते हैं। इसका कारण इन फंडों का निवेश पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप फंड मजबूत व्यावसायिक मॉडल वाली व आमतौर पर संबंधित क्षेत्रों में ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करते हैं। कुछ वर्षों में लार्ज कैप फंड्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने 3 और 5 वर्षों में क्रमशः 18.46 प्रतिशत और 22.43 प्रतिशत रिटर्न दिया। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप ने क्रमशः 16.68 प्रतिशत और 17.67 प्रतिशत का रिटर्न दिया। निप्पॉन लार्ज कैप फंड की सफलता का मुख्य कारण यह है कि यह इंडेक्सिंग के बजाय निवेश के सिद्धांत का पालन करता है, जहां फंड मैनेजर बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करता है।

डिमांड में है शेयर

अडानी की झोली में आई एक और बड़ी कंपनी

नई दिल्ली, एजेंसी।
गौतम अडानी समूह की कंपनी- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) की झोली में एक और कंपनी आई है। दरअसल, अडानी की कंपनी ने पीएफसी कंसल्टिंग से केपीएस 111 ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह अधिग्रहण एईएसएल की अपने शेयरधारकों के लिए विस्तार और अधिग्रहण के माध्यम से मूल्य बढ़ाने की रणनीति को और आगे बढ़ाएगा। हालांकि कंपनी ने डील की राशि का खुलासा नहीं किया। इस परियोजना का उद्देश्य 2.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें खावड़ा की चरण-5 योजना शामिल है। इसे खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से

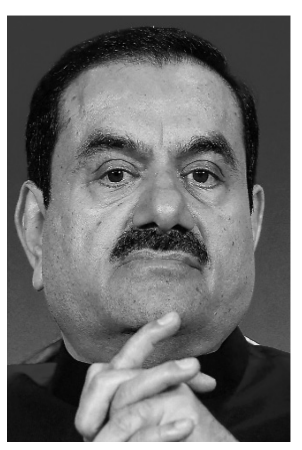

अतिरिक्त आठ गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की निकासी को सक्षम करने के लिए योजनाबद्ध किया गया है।

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में तेजी देखी गई। शुक्रवार को यह शेयर 1.23 प्रतिशत चढ़कर 1011.75 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1050 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 639.35 रुपये है। एनर्जी सॉल्यूशंस ने 18,000 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है। इसमें अलग-अलग परियोजनाओं पर पहले ही खर्च किए जा चुके 6,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। बीते दिनों कंपनी के सीईओ कंदर्प पटेल ने बताया था कि समूचे वर्ष के लिए हम ट्रांसमिशन में करीब 11,400 करोड़ रुपये, वितरण में 1,600 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग में 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इस प्रकार स्मार्ट मीटरिंग में हम करीब 2,000 करोड़ रुपये जोड़ेंगे। दूसरी तिमाही में वितरण में करीब 1,100 करोड़ रुपये और ट्रांसमिशन में लगभग 8,000 करोड़ रुपये रखे गए।

अजय देवगन ने खरीद रखा है पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल का शेयर- नई दिल्ली, एजेंसी। फिल्म प्रॉडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर शुक्रवार को क्व्स्थ में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 43.25 रुपये पर बंद हुए हैं। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयरों ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों में मार्च 2019 से लेकर अब तक 5300 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने भी पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर खरीद रखे हैं। अजय देवगन का कंपनी पर बड़ा दांव है। पैनोरमा स्टूडियोज अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने हाल में 5 फ्री शेयर बांटे हैं।

एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी

15 दिसंबर से लोन लेना हुआ सस्ता

इंडियन ओवरसीज बैंक का भी ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी।
देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेट में कटौती के बाद अपनी लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, जिससे मौजूदा और नए कर्जदारों के लिए लोन सस्ता हो गया है। इस लेटेस्ट कटौती के साथ एसबीआई का एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट 25 बेसिस पॉइंट्स कम होकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगा। संशोधित दरें 15 दिसंबर, 2025 से लागू होंगी।

बैंक ने सभी टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट में भी 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। इस संशोधन के साथ, एक साल की मैच्योरिटी वाला एमसीएलआर मौजूदा 8.75 प्रतिशत से घटकर 8.70 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह, एक साल की मैच्योरिटी दर क्रमशः 5 प्रतिशत सस्ती होकर 8.75 प्रतिशत और 8.80 प्रतिशत हो जाएगी। बैंक ने कहा कि उसने बेस रेट/ को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 9.90 प्रतिशत कर दिया है, जो 15 दिसंबर से प्रभावी होगा। इसके अलावा, बैंक ने 15 दिसंबर से प्रभावी दो साल से कम तीन साल की मैच्योरिटी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट दर में भी 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके 6.40 प्रतिशत करने का फैसला किया है। हालांकि, बैंक ने दूसरी मैच्योरिटी बकेट पर ब्याज दरें बरकरार रखी हैं। एसबीआई ने 444 दिन की खास स्कीम अमृत वृष्टि की ब्याज दर में भी कटौती की है। अब ब्याज दर 15 दिसंबर से 6.60 प्रतिशत से घटाकर 6.45 प्रतिशत कर दी गई है।

एक और सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी 15 दिसंबर, 2025 से अपनी लेंडिंग रेट में कमी की घोषणा की है। आइओबी ने एक बयान में कहा कि बैंक ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट - खासकर रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 8.35 प्रतिशत से 8.10 प्रतिशत कर दिया है, जिससे पॉलिसी रेट में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। इसके अलावा, बैंक की एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ने तीन महीने से लेकर तीन साल तक की सभी टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट में 5 बेसिस पॉइंट की कमी को मंजूरी दी है। बैंक ने कहा कि इन बदलावों से मौजूदा और नए दोनों तरह के कर्जदारों की इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी।

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की तरफ सेवरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर रेल्वे अंबाला छवानी द्वारा मण्डल के निम्नलिखित स्टेशनों पर ठेके आवंटित करने हेतु **ई–नीलामी** रेलवे वेबसाइट **www.ireps.gov.in**, के माध्यम से बोली आमंत्रित की जा रही है। आवंटित की जाने वाले ठेको का विवरण निम्नलिखित है।

नीलामी काटलोगस	कार्य का विवरण	नीलामी तिथि व समय
PnU-UMB-SIR-WRL-60-25-2	सरहिंद रेलवे स्टेशन पर 3 मीटर x 5.37 मीटर आकार (कुल क्षेत्रफल 16.11 वर्ग मीटर) वाले क्लोक रूम प्रबंधन एवं स्टेशनरी दुकान जिसमें मुद्रण/ फोटोकॉपी सुविधा उपलब्ध है, के लिए अनुबंध	23.12.2025 10.00.00
PnU-UMB-RPJ-WRL-59-25-2	राजपुरा रेलवे स्टेशन पर 3 मीटर x 4 मीटर आकार (कुल क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर) वाले क्लोक रूम प्रबंधन एवं स्टेशनरी दुकान जिसमें मुद्रण/ फोटोकॉपी सुविधा उपलब्ध है, के लिए अनुबंध	23.12.2025 10.00.00
PnU-UMB-UMB-WRL-47-25-1	अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर 12 फीट x 12 फीट आकार (कुल क्षेत्रफल 144 वर्ग फुट या 13.38 वर्ग मीटर) वाले क्लोक रूम प्रबंधन एवं स्टेशनरी दुकान जिसमें मुद्रण/ फोटोकॉपी सुविधा उपलब्ध है, के लिए अनुबंध	23.12.2025 10.00.00
PnU-UMB-SML-WRL-49-23-1	शिमला रेलवे स्टेशन पर 144 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले क्लोक रूम प्रबंधन के लिए अनुबंध	23.12.2025 10.00.00
PnU-UMB-SRE-WRL-44-25-1	सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर कुल क्षेत्रफल 20.44 वर्ग मीटर के साथ क्लोक रूम प्रबंधन सह स्टेशनरी दुकान जिसमें मुद्रण/ फोटोकॉपी सुविधा है	23.12.2025 10.00.00
PnU-UMB-BTI-WRL-66-25-1	बठिंडा रेलवे स्टेशन पर 20.78 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले क्लोक रूम प्रबंधन एवं स्टेशनरी दुकान जिसमें मुद्रण/ फोटोकॉपी सुविधा उपलब्ध है, के लिए अनुबंध	23.12.2025 10.00.00

नीलामी लीजिंग आमंत्रण सूचना, नीलामी प्रपत्र, एक बार पंजीकरण व अधिक जानकारी हेतु, रेलवे वेब साईट **www.ireps.gov.in** पर जाये।

3864/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

इस ट्रिक से करें कैट की तैयारी

एमबीए करने के लिए कई लोग आईआईएम जैसे संस्थान से पढ़ाई करना चाहते हैं। आईआईएम में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं हैं। इसके लिए आपको कैट की तैयारी करनी होती हैं। कई लोग कैट का एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेते हैं। वहीं कई लोग 2 साल तक तैयारी करते हैं लेकिन इसके बाद भी कैट के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे आप आसानी से कर सकते हैं कैट की तैयारी।

क्या आईआईएम में एडमिशन लेना है आसान

आईआईएम से पढ़ने का सपना हर किसी का होता है। ऐसे में इस कॉलेज में एडमिशन लेना काफी छात्र चाहते हैं लेकिन हर किसी का एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो पाता है।

कैट का एग्जाम कब होता है

आईआईएम तक पहुंचने के लिए कैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। हर साल कैट की परीक्षा नवंबर महीने से दिसंबर महीने के बीच होती है। वहीं इसके ऑनलाईन फॉर्म अगस्त के आसपास उपलब्ध होते हैं।

एग्जाम पैटर्न

इस परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यह परीक्षा के तीन भागों में बांटा जाता है और आपको हर एक भाग के लिए 60 मिनट का समय भी दिया जाता है। कुल मिलाकर आपको 180 मिनट मिलते हैं और आपको 180 मिनट में 100 सवालों के जवाब देने होते हैं।

कैट का एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें

कैट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको रोजाना छह से आठ घंटे पढ़ाई करनी होगी। अगर आप कैट के लिए अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप महज 6 महीने में कैट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कैट की तैयारी के लिए आप कोचिंग भी कर सकते हैं।

विषय की पूरी जानकारी हैं जरूरी

आप जिस भी विषय की पढ़ाई कर रहे हो आपको उस विषय में अच्छी पकड़ रखनी होगी। पढ़ने के बाद उसी विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का हल करें।

इंग्लिश पर दें ध्यान

आपको अपनी इंग्लिश पर भी ध्यान देना चाहिए। कैट के एग्जाम में थोड़ी टफ इंग्लिश पूछी जाती है इसलिए इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से करें। रोजाना इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़े और ज्यादा से ज्यादा अपनी वोकैबलरी पर काम करे।

शॉपिंग को बनाए अपना करियर ऑप्शन

ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें शॉपिंग करना काफी अच्छा लगता है। जिसमें वे ढेर सारे पैसे खर्च कर देते हैं। हालांकि, ऐसे कई करियर ऑप्शन होते हैं, जो शॉपहॉलिक इंसान के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं।

करियर ऑप्शन चुनते समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी पसंद-नापसंद और स्वभाव को जरूर देखें। हर व्यक्ति अलग तरह का होता है और इसलिए अगर वह अपने अनुसार करियर ऑप्शन चुनता है तो वह सफलता के नए मुकाम हासिल करता है। मसलन, अगर आप शॉपहॉलिक हैं तो ऐसे में आप अपने काफी सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग में ही खर्च कर देते हैं। जिससे बाद में आपको दुख होता है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते हैं।

ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इसी आदत को अपना करियर ऑप्शन बना लें। जी हां, आज के समय में एक शॉपहॉलिक व्यक्ति के लिए भी करियर ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। ऐसा व्यक्ति फैशन, ट्रेंड और रिटेल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है।

इससे ना केवल उन्हें शॉपिंग को एन्जॉय करने का मौका मिलता है, बल्कि इसके लिए वे अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जो एक शॉपहॉलिक व्यक्ति के लिए बेहतर ऑप्शन रहेंगे

फैशन बायर

एक शॉपहॉलिक व्यक्ति के लिए फैशन बायर बेहतरीन करियर ऑप्शन है। जो फैशन बायर होता है, वह रिटेल स्टोर्स के लिए कपड़े व एक्सेसरीज खरीदता है। इसके लिए जरूरी है कि वह लेटेस्ट फैशन ट्रेन्ड्स की जानकारी रखता हो। साथ ही साथ, सप्लायर्स से नेगेशिएट करने से लेकर सेल्स डाटा को एनालाइज कर सके। एक सक्सेसफुल फैशन बायर बनने के लिए आपको कस्टमर्स की पसंद-नापसंद का अंदाजा लगाना आना बेहद जरूरी है। अगर आप बतौर फैशन बायर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आप फैशन मर्चेंडाइजिंग, बिजनेस या उससे संबंधित फील्ड में डिग्री हासिल करें।

पर्सनल शॉपर

अगर आपको फैशन की गही समझ है और आप लेटेस्ट ट्रेन्ड्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं तो ऐसे में पर्सनल शॉपर या स्टाइलिस्ट बनकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे पर्सनल शॉपर अपने क्लाइंट के लिए कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज तक के लिए शॉपिंग करता है। उसका काम अपने क्लाइंट की पसंद-नापसंद को समझते हुए उसके ओवरऑल स्टाइल को इंप्रूव करना होता है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए किसी कोर्स को करने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फैशन व स्टाइलिंग से जुड़ा कोर्स आपको पर्सनल स्टाइलिंग की बेहतर समझ देगा।

फैशन ब्लॉगर

फैशन ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर बनकर भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक फैशन ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर स्पोन्सर्ड कंटेंट की मदद से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वे लोगों को बेहतर तरीके से स्टाइल करने के टिप्स देते हैं और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद लेते हैं। अगर आप बतौर फैशन ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर काम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग शुरू करें। इसमें आप हाई क्वालिटी कंटेंट पेश करें। जिससे लोग आपसे जुड़ने लगें और कई ब्रांड्स आपके साथ कोलेबोरेशन करना चाहें।

फैशन इवेंट को- ऑर्डिनेटर

एक शॉपहॉलिक व्यक्ति फैशन इवेंट को-ऑर्डिनेटर बनकर भी अपना करियर आगे बढ़ा सकता है। इनका मुख्य काम फैशन शो, प्रोडक्ट लॉन्च या अन्य फैशन से जुड़े इवेंट को प्लॉन व को-ऑर्डिनेट करना होता है। इस भूमिका में लॉजिस्टिक्स से लेकर मार्केटिंग तक कई चीजों को हैंडल करना होता है। इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग से इससे जुड़े फील्ड में डिग्री हासिल करके आप इस फील्ड में अपना कदम रख सकते हैं।

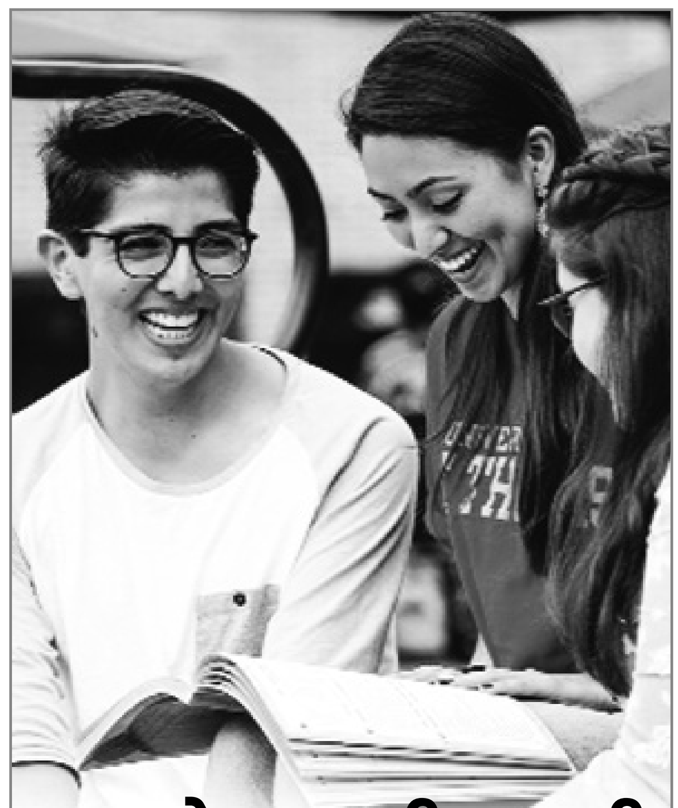

स्टूडेंट्स की काफी मदद करते हैं फेलोशिप प्रोग्राम

भारत समेत तमाम देशों में कई सारे फेलोशिप प्रोग्राम चलते हैं, जो स्टूडेंट्स की काफी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में विस्तार से।

आज जीवन में सफलता पानेवके लिए जरूरी है कि आप किताबी ज्ञान के साथ-साथ और भी पहलूओं को समझें। भारत में ढेर सारी फेलोशिप ऑफर की जाती है, जिनका आप हिस्सा बनकर खुद को अन्य लोगों ने अलग दिखा सकते हो। अब सवाल यह है कि भारत में कौन-कौन सी फेलोशिफ ऑफर की जाती है और उसका हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप

प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई है। यह योजना उच्च शिक्षण संस्थानों को लक्षित करती है। यह फेलोशिप विशेष रूप से पीएचडी करने वालों के लिए तैयार की गई है। इस फेलोशिप के तहत उम्मीदवारों को 70 हजार तक की राशि दी जाती है।

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने के इच्छुक लोगों के लिए। 4 से 10 साल के कार्य अनुभव वाले लोगों के लिए डिज़ाइन इसे डिजाइन किया गया है। फेलोशिप प्रतिभागियों को सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है।

इंडिया फेलो प्रोग्राम

इंडिया फेलो प्रोग्राम 18 महीने की अवधि की होती है और इस फेलोशिप में प्रतिभागियों को जमीनी स्तर पर सामाजिक चुनौतियों से जुड़ने के लिए तैयार करती है। किसी भी विषय से स्नातकों या जल्द ही स्नातक होने वाले लोगों के लिए खुला, यह कार्यक्रम व्यक्तियों को सामाजिक नेताओं में ढालता है, वास्तविक दुनिया के मुद्दों और समाधानों की गहरी समझ को बढ़ावा देता है।

एसबीआई फेलोशिप

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फ़ेलोशिप शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के राष्ट्र के आह्वान की प्रतिध्वनि है। यह फ़ेलोशिप प्रतिभाशाली दिमागों को ग्रामीण समुदायों के साथ सहयोग करने और सतत विकास समाधान बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। 13 महीने तक चलने वाला यह कार्यक्रम परिवर्तनकारी सीखने के अनुभवों को विकसित करता है, सहानुभूति को बढ़ावा देता है और ग्रामीण भारत की जटिलताओं को समझने वाले नेताओं का पोषण करता है।

बेकिंग प्रोफेशनल के पास अवसरों की कमी नहीं

अगर आपको बेकिंग करना काफी अच्छा लगता है और आपने इससे जुड़ा प्रोफेशनल कोर्स किया है तो अब आप कई जगहों पर काम के अवसर तलाश कर सकते हैं।

जब भी हम किसी खास अवसर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ ना कुछ मीठा अवश्य खाते हैं। आज के समय में लोग इस तरह के अवसर पर केक काटते हैं या फिर पेस्ट्री आदि खाकर सेलिब्रेट करते हैं। जिसके लिए अक्सर पेस्ट्री शॉप का रुख करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सिर्फ केक या पेस्ट्री खाना ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाना भी काफी अच्छा लगता है। ऐसे में बेकिंग एंड पेस्ट्री में प्रोफेशनल कोर्स करते हैं।

हो सकता है कि आपको यह लगता हो कि बेकिंग एंड पेस्ट्री कोर्स करके आप सिर्फ शॉप में ही काम कर सकते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आपने बेकिंग में प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आपके पास अवसरों की कमी नहीं है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि बेकिंग एंड पेस्ट्री कोर्स करने के बाद आप कहां-कहां अपना करियर देख सकते हैं-

बेकर

अगर आपने बेकिंग एंड पेस्ट्री में प्रोफेशनल कोर्स किया है तो ऐसे में आप बतौर बेकर या पेस्ट्री शेफ के रूप में काम कर सकते हैं। आप बेकरी, स्वीट शॉप या फिर रेस्त्रां आदि में काम कर सकते हैं। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अलग-अलग तरह की ब्रेड, पेस्ट्री, केक और अन्य बेक किए गए सामान को तैयार करना और उसे पकाना शामिल हो सकता है।

केक डेकोरेटर

केक डेकोरेटर एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, जिसका मुख्य कारण केक आदि की डिजाइनिंग व डेकोरेशन के लिए यूनिक आइडियाज तैयार करना होता है। खासतौर से, विशेष अवसरों के लिए वे खास डिजाइन तैयार करते हैं। आप बतौर केक डेकोरेटर बेकरी या केक शॉप्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।

चॉकलेटियर

बेकिंग एंड पेस्ट्री में प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप चॉकलेटियर बनकर भी अपना करियर देख सकते हैं। एक चॉकलेटियर का काम होता है कि वह कई अलग-अलग चॉकलेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें चॉकलेट के अलावा ट्रफ़ल्स और अन्य कन्फेक्शन शामिल हैं। एक चॉकलेटियर चॉकलेट प्रोडक्ट्स को बनाने के साथ उन्हें डिजाइन करने और उन्हें डेकोरेट करने का काम भी करता है।

फूड स्टाइलिस्ट

बेकिंग और पेस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद आप बतौर फूड स्टाइलिस्ट बनकर काम कर सकते हैं। यहां पर आप अपने बेकिंग स्किल्स को काम में ला सकते हैं। एक फूड स्टाइलिस्ट का काम फोटोग्राफर व डिजाइनर के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका मुख्य काम एडवरटाइजमेंट, कुकबुक और मैगजीन के लिए फूड आइटम्स को और भी ज्यादा अपीलिंग बनाना होता है।

फूड ब्लॉगर

अगर आपको लिखना अच्छा लगता है और आप अपने लेखन में अपने बेकिंग स्किल्स को भी शामिल करना चाहते हैं तो ऐसे में फूड ब्लॉगर बनकर भी अपना करियर संवार सकते हैं। जब आप बेकिंग एंड पेस्ट्री में प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आपका ज्ञान आपके लेखन को और भी अधिक बेहतर व गहन बनाता है। आप ब्लॉग से लेकर यूट्यूब या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्मों पर आपकी बेक्ड आइटम्स की रेसिपी, ट्यूटोरियल व सीक्रेट्स आदि शेयर कर सकते हैं।

क्रिकेट जगत में हड़कंप!

4 भारतीय खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का आरोप, बोर्ड ने किया सस्पेंड

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर ईमानदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के दौरान सामने आए एक गंभीर मामले में असम क्रिकेट एसोसिएशन ने सख्त कदम उठाते हुए चार खिलाड़ियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के चलते यह कार्रवाई की गई है, जिसने टूर्नामेंट की निष्पक्षता पर गहरी चिंता पैदा कर दी है।

चार खिलाड़ियों पर गिरी गाज

निलंबन की कार्रवाई जिन खिलाड़ियों पर हुई है, उनमें ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी, अमित सिन्हा और अभिषेक ठाकुर शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने असम टीम से जुड़े खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उन्हें गलत दिशा में उकसाने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच खेले गए मुकाबलों के दौरान इन चारों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। जैसे ही यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, असम क्रिकेट एसोसिएशन ने बिना देरी किए अनुशासनात्मक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा बीसीसीआई की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट की जांच के बाद हुआ।

असम क्रिकेट एसोसिएशन का सख्त रुख

असम क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रेस बयान जारी कर साफ कहा है कि ऐसे कृत्य खेल की निष्पक्षता और भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं। हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए चारों खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान ये खिलाड़ी असम क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आयोजित किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने द. अफ्रीका के सीनियर स्पिनर को दी कप्तानी

एसए20 में बिखेगें जलवा

जोहानिसबर्ग, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के सीनियर स्पिनर केशव महाराज आगामी एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रिटोरिया कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। आयोजकों ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। महाराज सीमित ओवरों की क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 40 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम पर 38 विकेट दर्ज हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने एसए 20 में 33 मैचों में 7.3 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लिए हैं। एसए20 ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक महाराज खेल के विभिन्न प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अनुभव रखते हैं। इसके साथ ही संयम, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ टीमों का नेतृत्व करने का उनका शानदार रिकार्ड रहा है।'

विज्ञप्ति में कहा गया है, 'उनकी उपस्थिति से प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम को नए सत्र से पहले आवश्यक संतुलन और दिशा मिलती है।'

कैपिटल्स की नजरें एसए20 में अपने पहले खिताब पर टिकी हैं। वह 2023 में फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप से हार गया था।

सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप

अंतिम पंघाल ने जीता स्वर्ण, महिला टीम खिताब हरियाणा के नाम

नई दिल्ली, एजेंसी। दो बार की विश्व चैंपियनशिप विजेता अंतिम पंघाल ने शुक्रवार को हैदराबाद में शुरू हुई 2025 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिला 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। टूर्नामेंट के

पहले दिन महिला कुश्ती के सभी 10 भार वर्गों में मुकाबले हुए जहां देश की पहलवानों ने 2026 एशियाई खेलों और अगले ओलंपिक चक्र की तैयारी शुरू की।

प्रिया मलिक हारीं

रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी) का प्रतिनिधित्व कर रही ओलंपियन अंतिम पंघाल अब 55 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही हैं जबकि पहले वह 53 किलोग्राम में खेलती थीं। उनके अलावा मनीषा (57 किलोग्राम) और निशा दहिया (68 किलोग्राम) ने भी अपने-अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। प्रिया मलिक को 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हरियाणा की ज्योति बेरवाल से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

मानसी को कांस्य पदक

विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता मानसी ने 62 किलोग्राम वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान की अंजली ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि हरियाणा की रजनीता ने 59 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हरियाणा की पुलकित ने 65 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल की, जबकि सेना खेल संवर्धन बोर्ड (एसएससीबी) की दीक्षा ने 72 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

'गिल को बाहर करें और संजू को दें मौका'

तीसरे टी20 से पहले पूर्व भारतीय ने दोहरे मापदंड पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग इलेवन से शुभमन गिल को बाहर करके उनकी जगह संजू सैमसन को मौका देना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब भारतीय उप-कप्तान एशिया कप 2025 में वापसी के बाद से खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार फेल हो रहे हैं।

गिल को ड्रॉप करने का आ गया है समय- भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मुकाबले से पहले कैफ ने गौतम गंभीर के दोहरे मापदंडो पर भी सवाल उठाए और कहा कि संजू सैमसन प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार थे। कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि उप-कप्तान गिल को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने का समय आ गया है। गिल ने कई बार आक्रामक खेलने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहे। उन्होंने कहा कि सैमसन एक टॉप-क्वालिटी खिलाड़ी हैं जो ज्यादा मौकों के हकदार हैं। कैफ के मुताबिक गिल को बाहर करके किसी बेहतर खिलाड़ी को टीम में लाना टीम के हित में होगा।

कैफ ने कहा कि गिल ने सब कुछ ट्राई कर लिया है और मुझे लगता है कि अब उन्हें ब्रेक देने और खुद को साबित कर चुके खिलाड़ियों को आजमाने का समय आ गया है। संजू सैमसन एक टॉप-क्वालिटी खिलाड़ी हैं साथ ही उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं। दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले भी उप-कप्तानों को टीम से बाहर किया गया है। अगर गिल को आराम देना और किसी और को टीम में लाना टीम के हित में है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026:

फेडरर की संन्यास के बाद टेनिस कोर्ट पर ऐतिहासिक वापसी

नई दिल्ली, एजेंसी। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर जनवरी में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन की धरती पर लौटने जा रहे हैं। टूर्नामेंट आयोजकों ने पुष्टि की है कि फेडरर 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के आधिकारिक लॉन्च इवेंट 'बैटल ऑफ द वर्ल्ड नंबर-1ह्य' की अगुवाई करेंगे। यह खास आयोजन टूर्नामेंट की शुरुआत से एक दिन पहले, 18 जनवरी को मेलबर्न पार्क में होगा। यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलियन ओपन में औपचारिक ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इस दौरान रॉड लेवर एरिना में फेडरर को खास श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिन्होंने अपने करियर में यहां छह बार नॉर्मन ब्रूक्स ट्रॉफी जीती थी। फेडरर 2022 में संन्यास के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित कोर्ट पर नजर आएंगे।

सितारों से सजा मुकाबला, अगासी-राफ्टर-हेविट भी होंगे शामिल- इस खास इवेंट में फेडरर के साथ चार बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन आंद्रे अगासी, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट राफ्टर और लेटन हेविट भी हिस्सा लेंगे। यह मुकाबला टेनिस प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव बनने वाला है।

फेडरर की भावुक प्रतिक्रिया- रोजर फेडरर ने कहा, 'मुझे आज भी याद है जब मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को 'हैप्पी स्लैम' कहा था। रॉड लेवर एरिना पर बिताए गए पल मेरे लिए बेहद खास रहे हैं। छह बार ट्रॉफी उठाने की खुशी, महान खिलाड़ियों से मुकाबले और ऑस्ट्रेलियाई फैंस का प्यार-सब कुछ अविस्मरणीय है। उन्होंने 2017 और 2018 में लगातार खिताब जीतने को अपने करियर की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक बताया।

गोल्फ में लहराया भारत का परचम

युवराज संधू ने जीता विश्वा समुद्र ओपन का खिताब

नई दिल्ली, एजेंसी। चंडीगढ़ के युवा गोल्फर युवराज संधू ने जबरदस्त वापसी करते हुए विश्वा समुद्र ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। पिछले सप्ताह उपविजेता रहने की निराशा को पीछे छोड़ते हुए संधू ने शुक्रवार को फाइनल राउंड में शानदार छह अंडर 66 का स्कोर खेला और कुल आठ शॉट्स की बड़ी जीत दर्ज की।

चार राउंड में 73-69-66-66 का कार्ड खेलते हुए संधू ने टूर्नामेंट को 14 अंडर 274 के कुल

स्कोर के साथ खत्म किया। लगातार दूसरे दिन बोगी-फ्री राउंड खेलना उनकी जीत की बड़ी वजह रहा। इस जीत के साथ 28 वर्षीय युवराज संधू ने 30 लाख रुपये की विजेता राशि हासिल की और उनकी कुल कमाई बढ़कर 1 करोड़ 61 लाख 67 हजार 100 रुपये हो गई, जिससे उन्होंने क्क्रअद्ब रैंकिंग में अजेय बढ़त बना ली। विश्वा समुद्र ओपन का खिताब जीतने के साथ ही संधू ने 2025 ऑर्डर ऑफ मेरिट भी अपने नाम किया और अगले सीजन के लिए छ्क्कवर्ल्ड टूर में अपनी जगह पक्की कर ली। यह संधू की इस सीजन की छठी जीत रही, जिसके साथ उन्होंने 2022 में मनु गांदस द्वारा बनाए गए एक सीजन में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके अलावा, उन्होंने डीजीसी में सबसे कम विजयी स्कोर (14 अंडर 274) का रिकॉर्ड भी छू लिया, जो पहले 2021 में विराज मदप्पा ने बनाया था। श्रीलंका के एन. थंगराजा ने छह अंडर 282 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और 20 लाख रुपये की उपविजेता राशि जीती।

कैमरन ग्रीन को 21 करोड़, तो पृथ्वी शॉ को भी मिला खरीदार, ऑक्शन से पहले बड़ा खेल

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में होगा. इस बार ऑक्शन के लिए कुल 359 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. मगर इसमें भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 77 खिलाड़ियों को ही खरीदा जा सकेगा. इस दौरान 10 टीमों के बीच स्टार खिलाड़ी खरीदने के लिए जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी. इस मिनी ऑक्शन से पहले पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक मॉक ऑक्शन करवाया. इन दौरान फैंस ने आईपीएल की सभी 10 टीमों के लिए बोली लगाई, जहां कैमरन ग्रीन सबसे ज्यादा डिमांड में रहे.

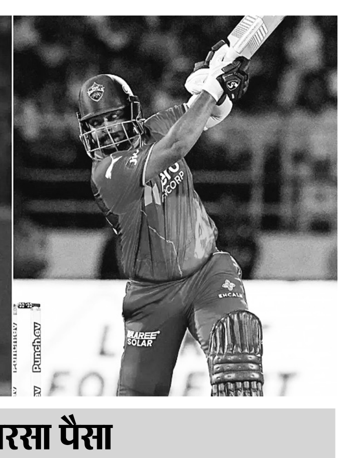

मॉक ऑक्शन में कैमरन ग्रीन पर बरसा पैसा

इस मॉक मॉक ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर सबसे ज्यादा बोली लगी. चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 21 करोड़ रुपए की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स भी जोरदार बोली लगा रही थी. दरअसल, इन दोनों ही टीमों को एक स्टार ऑलराउंडर की जरूरत है, ऐसे में मिनी ऑक्शन में भी कैमरन ग्रीन के लिए ऐसी लड़ाई देखने को मिल सकती है. इसके अलावा इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन भी काफी महंगे रहे. उनको कोलकाता ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए. वहीं, भारतीय युवा ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर भी कोलकाता की झोली में 17.5 करोड़ रुपए के साथ गिरे.

पृथ्वी शॉ को भी मिला खरीदार

एक समय भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर माने जाने वाले पृथ्वी शॉ को भी इस मॉक ऑक्शन में खरीदार मिला. पिछले साल मेगा ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था. लेकिन मॉक ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पृथ्वी को 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा. जिसका बाद उनकी आईपीएल में वापसी की उम्मीद बढ़ गई है. भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई भी महंगे रहे, हैदराबाद ने उन्हें 10.5 करोड़ रुपए में खरीदा.

खत्म हुआ इंतजार!

- 14 साल बाद भारत आए लियोनल मेसी, 3 दिन तक चलेगा GOAT इंडिया टूर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय फुटबॉल फैंस का एक लंबा इंतजार खत्म हो गया है. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी 14 साल बाद भारत आ गए हैं. वह 3 दिन तक भारत में रहने वाला है और तह्रञ्ज इंडिया टूर 2025' के तहत 4 शहरों में फैंस से मिलेंगे. वह देर रात 1.30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, उनके साथ पूर्व बार्सिलोना साथी लुईस सुवारेज और अर्जेंटीना टीम के साथी रोद्रिगो डे पॉल भी मौजूद रहे. टूर के पहले दिन लियोनल मेसी एक फुटबॉल मैच भी खेलने वाले हैं.

तह्रञ्ज इंडिया टूर 2025 की शुरुआत- कोलकाता में लियोनल मेसी का जोरदार स्वागत देखने को मिला. हाथों में अर्जेंटीना की जर्सी, झंडे, बैनर और पोस्टर लिए हजारों फैंस सड़कों पर जमा हो गए. इस दौरान 'मेसी-मेसी' के नारे लगाते हुए होटल हयात रीजेंसी के बाहर और लॉबी में फैंस घंटों इंतजार करते रहे. हालांकि सुरक्षा कारणों से मेसी को बैक एंट्रेंस से होटल में ले जाया गया, जिससे बाहर खड़े कई फैंस उनकी एक झलक नहीं पा सके.

श्रीलंका के सामने नहीं टिकी नेपाल, 8 विकेट से

अंडर-19 एशिया कप

दुबई, एजेंसी। अंडर-19 एशिया कप में नेपाल क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका ने लो स्कोरिंग रहे इस मैच में एकतरफा जीत दर्ज की। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। सेठमिका सेनेविरत्ने की घातक गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने नेपाल को महज 28.5 ओवर में 82 रन पर समेट दिया। किब्रिन श्रेष्ठ 18 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।

9 बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सके। नेपाल का स्कोर और भी कम होता, अगर श्रीलंका की तरफ से अतिरिक्त के रूप में 19 रन खर्च नहीं किए गए होते। सेठमिका सेनेविरत्ने नेपाल के लिए बेहद घातक साबित हुए। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 9.5 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्हें विकेट मिलता देख श्रीलंकाई कप्तान ने उनके ओवर नहीं रोके। नेपाल की पारी के कुल 28.5 ओवर में 9.5 ओवर सेनेविरत्ने ने फेंके। रसिथ निमारा, विग्नेश्वरन आकाश, दुलनिथ सिगेरा और चमिका हिनाटिगाला ने 1-1 विकेट लिए। 83 रन का लक्ष्य श्रीलंका के लिए किसी भी तरह से मुश्किल नहीं था और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इसे साबित भी किया। श्रीलंका ने मात्र 14.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर मैच जीत लिया। सलामी बल्लेबाज दिमंथा महाविथान ने 49 गेंद पर नाबाद 39 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 1 छक्का और 3 चौके निकले। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कविजा गामेज 29 गेंद पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। गामेज ने भी 1 छक्का और 3 चौके लगाए।

विरान चामुदिथा 10, और किथमा 2 के रूप में श्रीलंका को 2 झटके लगे। नेपाल के लिए दयानंद मंडल ने 1 विकेट लिया। एक विकेट रन आउट के रूप में गिरा।

महाराजा रणजीत सिंह एएफपीआई के पांच पूर्व विद्यार्थी भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना में हुए शामिल

अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को दी बधाई, राज्य का नाम रोशन करने के लिए किया प्रेरित

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में देश के लिए वीर सैनिक तैयार करने की पंजाब की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, मोहाली स्थित प्रतिष्ठित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज़ प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एमआरएसएएफपीआई) के पांच पूर्व विद्यार्थियों को आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है।

इंडियन मिलिट्री अकैडमी (आईएमए), देहरादून में 157वें रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड, जिसकी समीक्षा जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा की गई, के दौरान चार कैडेटों को भारतीय सेना में शामिल किया गया।

भारतीय सेना में शामिल होने वाले कैडेटों में गुरकीरत सिंह (अमृतसर), जिनके पिता कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के सेवानिवृत्त सैनिक हैं; बरजिंदर सिंह (गुरदासपुर), जिनके पिता स्कूल प्रिंसिपल और माता पीएसपीसीएल सुपरडेंट हैं; सुखदेव सिंह गिल (गुरदासपुर), जिनके पिता सेवानिवृत्त पीएसपीसीएल जेई हैं; तथा विनायक शर्मा (पठानकोट), जिनके माता-पिता निजी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, शामिल हैं।

एक अन्य कैडेट, कुश पांड्या (लुधियाना), को हैदराबाद के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स अकैडमी (एएफए) में 216वें कोर्स से भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया। इस परेड का निरीक्षण जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किया गया। कुश भारतीय सशस्त्र सेनाओं में विशिष्ट सेवाएं देने वाले परिवार से संबंधित हैं। उनके पिता सेवानिवृत्त आईएएफ ग्रुप कैप्टन हैं और उनकी माता आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।

पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने एमआरएसएएफपीआई के पूर्व कैडेटों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कैडेटों को अधिकारियों के रूप में अपने करियर में और अधिक मेहनत करने तथा पंजाब का सिर और ऊंचा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उन्हें सशस्त्र सेनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर रही है।

महाराजा रणजीत सिंह एएफपीआई के निदेशक, मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वीएसएम (सेवानिवृत्त) ने पूर्व कैडेटों को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए उन्हें भारतीय रक्षा सेवाओं के आदर्शों पर खरा उतरने तथा देश, राज्य और संस्थान का मान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इन पांच कैडेटों की नियुक्ति के साथ अब तक एमआरएसएएफपीआई के कुल 186 कैडेट भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो चुके हैं।

'युद्ध नशों विरुद्ध': 287वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 725 ग्राम हेरोइन सहित 27 नशा तस्कर गिरफ्तार

'डी-एडिक्शन' के तहत पंजाब पुलिस ने 15 व्यक्तियों को नशा मुक्ति उपचार के लिए किया राज़ी

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम 'युद्ध नशों विरुद्ध' को लगातार 287वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 178 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 25 एफआईआर दर्ज कर 27 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 287 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 40,209 हो गई है। इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 725 ग्राम हेरोइन, 500 ग्राम अफीम तथा 75 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध इस मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। इस ऑपरेशन के दौरान 36 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 80 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 178 छापेमारी की। दिन भर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 186 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति–इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)–लागू की गई है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 'डी-एडिक्शन' भाग के अंतर्गत 15 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी किया है।

पंजाब भर में आयोजित हुई चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत

429 लोक अदालत बेंचों का किया गया गठन

4.54 लाख से अधिक मामलों का निपटारा; 665 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित

जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, होशियारपुर ने 16 साल पुराने भूमि विवाद का किया निपटारा

चंडीगढ़। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में प्रदेश भर में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य विवादों का शीघ्र, कम खर्च में और मैत्रीपूर्ण तरीके से निपटारा करना है, ताकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अनुरूप न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ किया जा सके।

लोक अदालत में वादकारी, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता तथा सहयोगी भागीदारों ने भाग लिया। इस दौरान सिविल, वैवाहिक, संपत्ति, मोटर दुर्घटना दावा, बैंकिंग, बीमा सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत ने वादकारियों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रदेश के सभी जिलों और उप-मंडलों में कुल 429 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 5,11,015 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से 4,54,466 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया तथा 665 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रदेश भर के हजारों वादकारियों को कम समय में अपने विवादों का समाधान प्राप्त हुआ। इस दौरान एक दशक से अधिक पुराने विवादों सहित कई लंबित मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिससे न्यायालयों पर मामलों का बोझ काफी हद तक कम हुआ।

बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों और आम जनता की ओर से लोक अदालतों को भरपूर सहयोग मिला, जो लोक अदालतों में लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, होशियारपुर ने भूमि विभाजन से संबंधित 16 वर्ष पुराने सिविल अपील का सफलतापूर्वक निपटारा किया। यह मामला वर्ष 2009 में दायर हुआ था और प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री सहित कई चरणों से गुजर चुका था। लोक अदालत के पूर्व निरंतर प्रयासों के माध्यम से इसे आपसी सहमति से सुलझाया गया। समझौते के अनुसार पक्षकारों ने धनराशि के लेन-देन के माध्यम से विवादित भूमि के एक हिस्से पर स्वामित्व अधिकार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की, जिससे लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हुआ और पक्षकारों के बीच सद्भाव बहाल हुआ। अंततः इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपील का निपटारा कर दिया गया।

इस अवसर पर पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा ने प्रदेश भर के न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों और स्वयंसेवकों के समर्पित प्रयासों की सराहना की, जिनकी सामूहिक प्रतिबद्धता से यह मेगा कार्यक्रम सफल हो सका।

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों, राज्य न्यायपालिका, बार सदस्यों, पुलिस अधिकारियों तथा सिविल प्रशासन का उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद किया।

डीसी की बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे खाद वितरण के अधिकारी

भिवानी, । जिले में उर्वरकों, विशेषकर यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, पारदर्शी वितरण एवं सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को लेकर डीसी साहिल गुप्ता ने कृषि विभाग को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोई भी फर्टिलाइज़र निरीक्षक अथवा अधिकारी डीसी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

डीसी के आदेशों के चलते कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ विनोद फोगाट ने जिले के सभी फर्टिलाइज़र निरीक्षकों को अपने-अपने ब्लॉक एवं उपमंडल क्षेत्रों में पूर्ण सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि उर्वरकों से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी, टैगिंग, अवैध भंडारण अथवा लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध तत्काल पुलिस कार्रवाई अथवा नियमानुसार अन्य कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में जिला स्तर के सभी अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी खाद विक्रय केंद्रों पर उपमंडल कृषि अधिकारियों (एसडीएओ) की ड्यूटी लगाकर निरंतर निगरानी की जा रही है तथा प्रत्येक एक से दो घंटे में रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में विभिन्न स्थानों से खाद की आपूर्ति हो रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल की स्थिति में भिवानी जिले में 3,639 मीट्रिक टन (एमटी) यूरिया उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हिसार से आने वाली यूरिया रेक का एक भाग भिवानी जिले के लिए भी निर्धारित किया गया है। भिवानी रेक प्वाइंट पर भी खाद प्राप्त हो रही है, जिसे शीघ्र ही फील्ड में वितरित किया जाएगा। साथ ही, खुदरा विक्रेताओं के पास पहले से ही पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि सभी संबंधित एसडीएओ, ब्लॉक नोडल अधिकारी एवं ब्लॉक कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक दुकान पर स्टॉक बोर्ड पर उपलब्ध खाद की मात्रा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। साथ ही गाँवों में मुनादी के माध्यम से खाद वितरण की जानकारी किसानों तक पहुँचाई जाए तथा मुनादी किए जाने की पुष्टि सरपंच से लिखित रूप में प्राप्त की जाए। यदि कोई विक्रेता किसानों को खाद देने से इंकार करता है अथवा यूरिया की कालाबाजारी या टैगिंग करता है, तो इसके लिए संबंधित एसडीएओ, ब्लॉक नोडल अधिकारी एवं ब्लॉक कृषि अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। विभाग ने किसानों किसान से अपील की है कि कृषि विभाग द्वारा यूरिया के सत्यापन हेतु संपर्क किए जाने पर सही जानकारी देकर सहयोग करें। यह संभव है कि खाद की जो कमी प्रतीत हो रही है, वह किसी असामाजिक तत्व द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य में सप्लाई कर दी गई हो। ऐसी स्थिति में सही जानकारी देकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसानों को यह भी सूचित किया जाता है कि यूरिया का निर्धारित मूल्य 266.50 रुपए प्रति बैग है। इससे अधिक मूल्य किसी भी स्थिति में न दें। यदि कोई थोक या खुदरा विक्रेता यूरिया के साथ किसी अन्य सामान या उत्पाद को जबरन लेने के लिए बाध्य करता है, तो इसकी सूचना तत्काल अखबारों एवं मीडिया में जारी हेल्पलाइन नंबरों पर दें।

मोहाली की दो लड़कियाँ भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुईं शामिल

अमन अरोड़ा ने महिला अधिकारियों को वायुसेना में उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए दी बधाई

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लड़कियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, माई भागो आर्म्ड फोर्सेज़ प्रिपरेटरी इंस्टिट्यूट (एएफपीआई) फॉर गर्ल्स, एसएएस नगर (मोहाली) ने एक शानदार सफलता हासिल की है। इस संस्थान की दो पूर्व छात्राएँ–चरनप्रीत कौर और महक दहिया–भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुई हैं। दोनों छात्राओं ने आज एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल (हैदराबाद) से सफलतापूर्वक पास आउट होकर अपने संस्थान का नाम रोशन किया।

उन्हें प्रभावशाली पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, जिसकी समीक्षा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम द्वारा की गई।

फ्लाइंग ऑफिसर चरणप्रीत कौर के पिता स हरमिंदर सिंह बनवैत एक ड्राइवर हैं और कुराली, एस.ए.एस. नगर के निवासी हैं, जबकि फ्लाइंग ऑफिसर महक दहिया के पिता श्री अनिल कुमार दहिया एक सरकारी अध्यापक हैं और एस.ए.एस. नगर के निवासी हैं।

फ्लाइंग ऑफिसर चरनप्रीत कौर को प्रशासनिक शाखा में शामिल किया गया है, जबकि फ्लाइंग ऑफिसर महक दहिया को वायुसेना की लेखा शाखा में नियुक्त किया गया है।

पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने फ्लाइंग ऑफिसर चरनप्रीत कौर और महक दहिया को उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पंजाब की अन्य लड़कियों को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा जुलाई 2023 में माई भागो एएफपीआई में लड़कियों के लिए एक एनडीए प्रिपरेटरी विंग भी स्थापित किया गया था, जिसका तीसरा बैच इस समय प्रशिक्षणाधीन है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक नए ब्लॉक–जिसका नाम फील्ड मार्शल एसएचएफजे मानेकशॉ के नाम पर रखा गया है–का उद्घाटन नवंबर 2025 में किया गया था।

माई भागो एएफपीआई के निदेशक मेजर जनरल जसबीर सिंह संधू, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने दोनों पूर्व छात्राओं के भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार के सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक लड़कियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों को बल देगी। उन्होंने दोनों महिला अधिकारियों को भारतीय वायुसेना में उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।

राष्ट्रीय लोक अदालत 18214 केसो का निपटान किया गया - सीजेएम पवन कुमार

भिवानी । हरियाणा राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि शनिवार को जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में भी इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। इससे अदालतों के लंबित मामलों में कमी आती है, क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की कार्यवाही को भी समाप्त कर पक्षों की सहमति से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है और त्वरित और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। विवाद के निपटारे के अलावा, पक्षकारों को मामलों की उनके द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी का लाभ होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन? कुमार ने कहा कि लोक अदालत में अपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए।

उपायुक्त की आमजन से अपील, समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का करवाएं निवारण

सोमवार व गुरूवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित किए जाते हैं समाधान शिविर

पंचकूला। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की। उन्होने बताया कि प्रत्येक सोमवार व गुरूवार को 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का लघु सचिवालय, सैक्टर-1 के सभागार में आयोजन किया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिलावासियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर समाधान शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। समाधान शिविर के आयोजन के पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जिलावासियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर न काटने पडे। उन्होने बताया कि संबंधित अधिकारी लोगों की समस्याओं के समाधान करने में कोई कोताही न बरतें। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि हम सभी जिलावासियों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए समाधान शिविर में अपनी उपस्थिति दर्शातें हैं, इसके अलावा हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी है कि हम सभी जिलावासियों की समस्याओं का तय समय में समाधान करें।

भिवानी में आज जुटेंगे 4 विधानसभाओं के शक्ति केंद्र प्रमुख, संगठन की मजबूती पर होगा जोर

शक्ति केंद्र प्रमुख पार्टी की रीढ़, आगामी रणनीतियों पर होगी चर्चा -वीरेंद्र कौशिक

भिवानी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भिवानी जिला इकाई द्वारा संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक धार देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिसंबर (शनिवार) को भिवानी के जिला भाजपा कार्यालय में जिले की चार प्रमुख विधानसभाओं भिवानी, बवानीखेड़ा, तोशाम और लोहारू के शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक विशेष बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश जारी करना है। बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और शक्ति केंद्र प्रमुख संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर की बैठक संगठन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में भिवानी, बवानीखेड़ा, तोशाम और लोहारू विधानसभा क्षेत्रों के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख हिस्सा लेंगे। हमारा लक्ष्य बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ को मजबूत करना और सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

पंचकूला में आयुर्वेद महोत्सव के 2025 बना जनआकर्षण का केंद्र, दूसरे दिन भी उमड़ी भारी भीड़

हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत

पंचकूला । सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित आयुर्वेद महोत्सव 2025 के दूसरे दिन भी आम जनता की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग बड़ी संख्या में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी लेने पहुंचे और प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों से आयुर्वेदिक उत्पाद खरीदते नजर आए। महोत्सव में लोगों के बीच आयुर्वेद के प्रति गहरी रुचि और जागरूकता देखने को मिली।

महोत्सव के दूसरे दिन हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने पंचकूला में इस प्रकार की आयुर्वेदिक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए महोत्सव के संचालकों को बधाई दी और आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार में उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में आचार्य मनीष भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ज्ञानचंद गुप्ता, आचार्य मनीष, भाजपा नेत्री रंजीता मेहता और ओमप्रकाश देवी नगर द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात महोत्सव के संचालकों ने मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों को शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

श्री गुप्ता ने कहा की आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। यह जीवन का एक दर्शन है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य सिखाता है। इसमें प्रकृति, स्वास्थ्य और मानव कल्याण की गहरी समझ समाहित है, जो रोकथाम, व्यक्तिगत देखभाल और सतत जीवन शैली पर बल देती है।

उन्होंने कहा की आयुर्वेद के सिद्धांत ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जो शाश्वत होने के साथ-साथ अत्यंत प्रासंगिक भी है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद महोत्सवङ्क2025 को वास्तव में विशिष्ट बनाने वाला पहलू इसमें सहभागिता की व्यापकता और गहराई है। उन्होंने आगे कहा कि शीर्ष शिक्षाविदों, आचार्यों और विद्वानों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि शास्त्रीय ग्रंथों और पारंपरिक ज्ञान की व्याख्या, विश्लेषण एवं अनुप्रयोग वैज्ञानिक सटीकता के साथ हो, जिससे प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण हो सके।

आचार्य मनीष ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और आयुर्वेदिक दवाइयां एवं उत्पाद बेचने वाले संस्थानों से उनके उत्पादों के लाभ, उपयोग और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एक विशेष सत्र भी दिया, जिसमें आयुर्वेद के फायदे बताते हुए कहा कि बदलती जीवनशैली और बढ़ती बीमारियों के बीच आयुर्वेद सबसे प्रभावी और भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आयुर्वेद का है और भारत के पास इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की अपार संभावनाएं हैं।

इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र संयोजक राजेश गोयल भी महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में जानकारी ली और स्वदेशी अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। महोत्सव के आयोजक ऋषभ दीक्षित ने बताया कि यह आयोजन समग्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। उनके अनुसार देशभर से आए विशेषज्ञ अपने शोध, अनुभव और आधुनिक दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं, जिससे आयुर्वेद का वैज्ञानिक आधार और भी मजबूत होगा।

कार्यक्रम में प्रमुख विशेषज्ञों के रूप में अजीत पाल सिंह, संचित शर्मा, तरनजीत सिंह भरना, रामपाल सोमानी और हितेश जानी उपस्थित रहे। इन विशेषज्ञों ने आयुर्वेद की आधुनिक दिशा, तकनीकी उन्नति और वैश्विक संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई।